



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 2018/श्रावण 10, 1940

No. 262]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 2018/SHRAVANA 10, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2018

(अंतिम जांच परिणाम)

**विषय:** सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों के संबंध में तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना।

**फा. सं. 7/16/2017-डीजीएडी.**—यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटन-रोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटन-रोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्टिक सोडा के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच की तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी।

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. यतः सऊदी अरब, ईरान, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26.05.2000 को अधिसूचना संख्या 56/1/1999-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 16.11.2000 के प्रारंभिक जांच परिणाम द्वारा अनन्तिम शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जिसे दिनांक 26.12.2000 की अधिसूचना संख्या 153/2000-सीमा-शुल्क द्वारा लगाया गया था। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम दिनांक 14.05.2001 को अधिसूचना संख्या 56/1/1999-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाने की

सिफारिश की गई थी। तदनुसार, शुल्क लगाने के लिए दिनांक 26.06.2001 की अधिसूचना संख्या 69/2001-सीमा-शुल्क (एडीडी) जारी की गई थी।

3. यतः 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी और अंतिम जांच परिणाम की दिनांक 1.8.2006 की अधिसूचना संख्या 15/29/2004-डीजीएडी द्वारा शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी। तदनुसार, उसे दिनांक 13.09.2006 की अधिसूचना संख्या 98/2006-सीमा-शुल्क द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब, कोरिया जनवादी गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के संबंध में एक मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की गई थी, जिसके अनुसरण में प्राधिकारी ने दिनांक 7 जुलाई, 2011 के अंतिम जांच परिणाम द्वारा शुल्कों की मात्रा में संशोधन किया था।

4. 5 वर्ष पूरा होने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 2.9.2011 की अधिसूचना संख्या 15/28/2010-डीजीएडी द्वारा सऊदी अरब, ईरान, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस से कार्बोनाट सोडा के आयातों पर दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 31.08.2012 की अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना संख्या 15/28/2010-डीजीएडी द्वारा सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों पर पाटन-रोधी शुल्कों को निरंतर जारी रखने की सिफारिश की थी। जब कि जापान से आयातों पर "शून्य" पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, फ्रांस पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया गया था। तदनुसार, शुल्क लगाने के लिए दिनांक 26.11.2012 की अधिसूचना संख्या 49/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी) जारी की गई थी, जो कि 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध थी।

5. प्राधिकारी ने दिनांक 22.01.2016 की अधिसूचना संख्या 15/19/2015-डीजीएडी द्वारा सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के खिलाफ एक अन्य मध्यावधिक जांच शुरू की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने तीन देशों नामतः सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में व्यापक जांच की थी और दिनांक 20.06.2017 की अधिसूचना संख्या 15/19/2015-डीजीएडी द्वारा सिफारिशें जारी की थीं। प्राधिकारी ने शुल्कों में संशोधन करने की सिफारिश की थी, जिसे दिनांक 23.08.2017 की सीमा-शुल्क की अधिसूचना संख्या 39/2017-सीमा-शुल्क (एडीडी) द्वारा अधिसूचित किया गया था।

6. यतः मेसर्स अलकाली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) ने मेसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (6 यूनिट) और मेसर्स एसआईईएल, केमिकल कॉम्प्लेक्स (जिसे आगे याचिकादाता भी कहा गया है) की ओर से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उसने पहले लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने तथा सऊदी अरब, जापान, ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों पर शुल्कों को निरंतर जारी रखने का अनुरोध किया था। ऐसा अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि इन उपायों में समाप्त हो जाने के फलस्वरूप इन देशों से पाटन होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

7. पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में निरंतर पाटन-रोधी लगाए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इसकी जांच करने के लिए कि यदि शुल्कों को हटा लिया जाता है, तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए दिनांक 20.11.2017 की अधिसूचना संख्या 7/16/2017-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। तथापि, ईरान और जापान से कोई पाटन और क्षति नहीं होने के पर्याप्त साक्ष्य की कमी होने के कारण उनके विरुद्ध कोई जांच शुरू नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त लगाए गए शुल्कों की अवधि को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 24.11.2017 की अधिसूचना संख्या 55/2017-सीमा-शुल्क (एडीडी) द्वारा 25.11.2018 तक बढ़ा दिया गया था।

8. वर्तमान समीक्षा जांच के दायरे में संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में विगत जांचों के सभी पहलु शामिल हैं।

#### ख. प्रक्रिया

9. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाई गई है :

- (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की ओर से याचिकादाता से एक लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जिसमें सऊदी अरब, ईरान, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर जारी रखने का अनुरोध किया गया है। लगाने की सिफारिश की गई

- (2) प्राधिकारी ने विधिवत् अधिप्रमाणित आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सऊदी अरब, ईरान, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के बारे में दिनांक 20.11.2017 को जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना संख्या 7/16/2017-डीजीएडी जारी की थी, जो कि भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई थी। पाटन और क्षति के पर्याप्त साक्ष्य की कमी होने के कारण जापान और ईरान के खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की गई थी।
- (3) नियम 6 (3) के अनुसार संबद्ध देशों के नई दिल्ली में स्थित दूतावासों को जांच शुरू करने की अधिसूचना और एनसीवी याचिका की प्रति प्रेषित करने के साथ निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के बाद में सूचित कर दिया गया है।
- (4) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्माताओं/निर्यातकों (जिनके नाम व पते याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए) को सार्वजनिक सूचना की प्रतियां भेजी गईं तथा नियम 6 (2) और 6 (4) के अनुसार पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया:-

- (क) मेसर्स शेल ट्रेडिंग (एम ई) प्रा. लि. (एसटीएमई) (व्यापारी), दुबई
- (ख) मेसर्स सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (है.क्वा.), सऊदी अरब
- (ग) मेसर्स सऊदी पेट्रोकेमिकल कंपनी, सऊदी अरब
- (घ) मेसर्स सहारा पेट्रोकेमिकल कंपनी, सऊदी अरब
- (ङ) मेसर्स सऊदी अरब सहारा एंड मेडन पेट्रोकेमिकल्स कंपनी, (सेमपेको), सऊदी अरब
- (च) मेसर्स मिड प्वाइंट केमिकल कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका
- (छ) मेसर्स यू एस एकजो केमिकल लिमिटेड संयुक्त राज्य अमेरिका
- (झ) मेसर्स डोव केमिकल कं., संयुक्त राज्य अमेरिका
- (ञ) मेसर्स ट्रिकोन एनर्जी, यूएसए
- (ट) मेसर्स एफएमजी इंडस्ट्रियल केमिकल्स ग्रुप, यूएसए

- (5) इसके अतिरिक्त कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित अवधि को भी 05.02.2018 तक बढ़ा दिया था।
- (6) निम्नलिखित उत्पादक और निर्यातक ने केवल निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-
- (क) मेसर्स सऊदी पेट्रोकेमिकल कंपनी (एसएडीएफ), (उत्पादक) ने अपने निर्यातक मेसर्स सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एसएबीआईसी), सऊदी अरब।
- (7) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं को (जिनके नाम व पते आवेदकों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) उपलब्ध कराए और उन्हें नियम 6 (4) के अनुसार, पत्र जारी होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का परामर्श दिया :-

- (क) मेसर्स अभय केमिकल्स लिमिटेड
- (ख) मेसर्स अलब्राइट विल्सन केमिकल्स लिमिटेड
- (ग) मेसर्स अरविंद मिल्स लिमिटेड
- (घ) मेसर्स बिरला सेलुलोस लिमिटेड
- (ङ) मेसर्स सेंट्रल पल्प मिल्स लिमिटेड
- (च) मेसर्स दीपक नाइट्रेट लिमिटेड

- (छ) मेसर्ज गोदरेज सोपास लिमिटेड
- (ज) मेसर्ज गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड
- (झ) मेसर्ज गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड
- (ञ) मेसर्ज इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर को ऑप. लि.
- (ट) मेसर्ज इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
- (ठ) मेसर्ज जयसिंथ डाइकैम लिमिटेड
- (ड) मेसर्ज लिंक फार्मा लिमिटेड
- (ढ) मेसर्ज मेघमणी आर्गेनिक्स लिमिटेड
- (ण) मेसर्ज नर्मदा केमेच्योर पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
- (त) मेसर्ज निरमा लिमिटेड
- (थ) मेसर्ज पब केमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड
- (द) मेसर्ज रामा न्यूज प्रिंट्स एंड पेपर्स लिमिटेड
- (ध) मेसर्ज रुबामिन लिमिटेड
- (न) मेसर्ज साबेरो आर्गेनिक्स लिमिटेड
- (प) मेसर्ज टोरेट गुजरात बायोटेक लिमिटेड
- (फ) मेसर्ज ट्रांसपेक सिलोक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (ब) मेसर्ज नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड
- (भ) मेसर्ज सायनाइड्स एंड केमिकल्स कंपनी
- (म) मेसर्ज हिल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- (य) मेसर्ज अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड
- (कक) मेसर्ज अडानी विलमर लिमिटेड
- (खख) मेसर्ज लिब्रा फोम्स
- (गग) मेसर्ज श्री रामचन्द्र स्ट्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड
- (घघ) मेसर्ज विलाग इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड
- (ङङ) मेसर्ज दोराते आर्गेनिक्स लिमिटेड
- (चच) मेसर्ज सीजे शाह एंड कंपनी
- (छछ) मेसर्ज हरीश कुमार एंड कंपनी
- (जज) मेसर्ज हिंदुस्तान लिंक एंड रेसिन लिमिटेड
- (झझ) मेसर्ज हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड
- (ञञ) मेसर्ज वेदान्ता लिमिटेड

- (8) सभी निर्यातकों में से केवल मेसर्ज वेदान्ता लिमिटेड ने उत्तर प्रस्तुत किया है। उसने आयातक की प्रश्नावली के प्रपत्र में उत्तर प्रस्तुत किया है और साथ ही मौखिक सुनवाई में भी भाग लिया है और बाद में लिखित निवेदन प्रस्तुत किए हैं।
- (9) सऊदी अरब की सरकार ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, लेकिन उसने कोई लिखित निवेदन प्रस्तुत नहीं किया था।
- (10) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन से जांच की अवधि अप्रैल, 2016 से जून, 2017 (15 महीनों) की है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच की अवधि शामिल है।

- (11) जांच की अवधि और विगत तीन वर्षों की अवधि के कारोबार-वार आयात संबंधी आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त किए गए थे और उन पर इस जांच में विश्लेषण के प्रयोजन से भरोसा किया गया है।
- (12) प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त, आंकड़ों, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों और सभी निवेदनों को निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण फोल्डर में खुला उपलब्ध कराया था, जिसमें अगोपनीय वृत्तान्त को नियम 6 (7) के अनुसार अनुरोध किए जाने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान किया गया था।
- (13) नियमावली के अनुबंध-2 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत का आकलन करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की यथा-संभव जांच की है।
- (14) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करने के लिए 07.05.2018 को एक मौखिक सुनवाई की थी। इस मौखिक सुनवाई के समय जिन सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए गए थे, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें।
- (15) इस जांच की कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों, दिए गए तर्कों और साक्ष्यों के साथ प्रदत्त सूचना को जहां कहीं भी प्रासंगिक पाया गया है, प्राधिकारी द्वारा उनका निदान इस प्रकटन विवरण में कर दिया गया है।
- (16) प्राधिकारी ने जांच की कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की परिशुद्धता की यथा-संभव स्वयं जांच की है, जो कि इस प्रकटन का आधार बनती हैं और वर्तमान जांच के प्रासंगिक है तथा प्राधिकारी ने इस प्रकटीकरण विवरण में उस पर उचित रूप से विचार किया है।
- (17) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय वृत्तान्त को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण करने के लिए एक सार्वजनिक फाईल के रूप में खुला उपलब्ध कराया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को प्रकटीकरण विवरण में शामिल किया गया है।
- (18) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर दाखिल सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
- (19) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अडचन डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपना निर्णय रिकार्ड किया है।
- (20) दिनांक 19.07.2018 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया था, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन ऐसे आवश्यक तथ्य शामिल थे, जो इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना का आधार बने। प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 25.07.2018 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुत टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- (21) इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में \*\*\* किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई सूचना को दर्शाता है।
- (22) प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए विनिर्णय दर 67.46 रुपए = 1 अमेरिकी डॉलर मानी गई है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का दायरा

घरेलू उद्योग के विचार

10. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद वही है, जो कि विगत जांच में था, अर्थात् उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे सामान्यतया सभी रूपों में कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। इसे रासायनिक रूप से NaOH के नाम से जाना जाता है और यह एक अजैविक, साबुन की तरह का क्षारीय तथा गंधहीन रसायन होता है, जिसका व्यापक रूप से उपयोग, विविध औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा कच्चे माल अथवा एक सहायक रसायन के रूप में किया जाता है।

- (ख) कास्टिक सोडा का दो रूप में उत्पादन होता है अर्थात् तरल और ठोस, जिसमें तीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाएं हैं, अर्थात् मरकरी सेल प्रक्रिया, डायाफ्राम प्रक्रिया और मेम्ब्रान प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं में अंतर होने से विभिन्न गुणों के संदर्भ में उत्पादन में अंतर नहीं होता है।
- (ग) कास्टिक सोडा ऐसा उत्पाद है जिसे, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लोर अलकाली प्रक्रिया, जिसमें मरकरी सेल प्रक्रिया, डायाफ्राम सेल प्रक्रिया और मेम्ब्रेन सेल प्रक्रिया शामिल है, के अंतर द्वारा 50% द्रव्य के रूप में औद्योगिक रूप से उत्पादित किया जाता है।
- (घ) जैसा कि विगत जांच में नोट किया गया है, याचिकादाता घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

#### प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई मामला नहीं उठाया है।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान मध्यावधिक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रॉक्साइड (रासायनिक नाम NaOH) है जिसे सामान्यतया सभी रूपों में कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है।

13. कास्टिक सोडा एक अजैविक, साबुन की तरह का क्षारीय तथा गंधहीन रसायन होता है तथा विभिन्न क्षेत्रों जैसे पल्प और पेपर के निर्माण, न्यूज प्रिंट, विस्कोस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्युमीनियम कॉटन, टेक्सटाइल्स, टॉयलेट तथा लॉन्ट्री साबुन, डिटर्जेंट, रंगाई, ड्रस एवं फार्मास्युटिकल्स, पैट्रोलियम रिफाइनरी इत्यादि में प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा का दो रूप में उत्पादन होता है अर्थात् तरल और ठोस, जिसमें तीन प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाएं हैं, अर्थात् मरकरी सेल प्रक्रिया, डायाफ्राम प्रक्रिया और मेम्ब्रान प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं में अंतर होने से विभिन्न गुणों के संदर्भ में उत्पादन में अंतर नहीं होता है।

14. कास्टिक सोडे को सीमा शुल्क शीर्ष 2815.11 और 2815.12 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत किया गया है। आईटीसी आठ अंकीय वर्गीकरण के अनुसार, उत्पाद को सीमा शुल्क शीर्षक 2815.1110, 2815.1120 तथा 2815.1200 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण संकेतात्मक है और यह वर्तमान जांच के दायरे में किसी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

15. चूंकि, किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध नहीं किया है, इसलिए इस वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही है।

#### घ. समान वस्तु

16. विगत जांचों में समान वस्तु के संबंध में जैसा नोट किया गया है, भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। हालांकि संबद्ध उत्पाद उत्पादन विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय वस्तुएं हैं। ये दोनों वस्तुएं वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। किसी भी प्रतिवादी पक्षकार ने इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए दावों पर कोई प्रतिवाद नहीं किया है।

17. याचिका कंपनियों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को प्राधिकारी द्वारा पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु माना जा रहा है।

#### ड. घरेलू उद्योग और आधार

#### घरेलू उद्योग के विचार

18. घरेलू उद्योग और उसके आधार के बारे में घरेलू उद्योग के विचार और उत्तर निम्नानुसार हैं:-

(क) घरेलू उद्योग की ओर से मेसर्स अलकाली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। लागत संबंधी आवश्यक सूचना प्रदान करके निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है:-

1. मेसर्स डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, साहूपुरम
2. मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसने विलायत, रेहला, कारवार, रेणुकूट, बेरावल और गंजम में स्थित अपने छः संयंत्रों के संबंध में भाग लिया है।

### 3. मेसर्ज एसआईईएल, केमिकल कॉम्पलेक्स

- (ख) कुल भारतीय उत्पादन में याचिकादाता कंपनियों का हिस्सा 25.06% बनता है और उन्हें ऐसे उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है, जिनका उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 100% बनता है। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदक कंपनियां, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर पात्र घरेलू उद्योग बनती हैं।
- (ग) नियम 2 (ख) में गणितकीय आंकड़ों के रूप में प्रमुख भाग की न्यूनतम अवसीमा का उल्लेख नहीं है। प्रमुख भाग का तात्पर्य भारतीय उत्पादन का 50% अथवा विशेषकर 25% से अधिक से नहीं है। इसके अतिरिक्त नियम 23 (1ख) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नियम 5 के प्रावधान निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में लागू नहीं होते हैं।
- (घ) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अनेक मामलों में प्रमुख भाग के रूप में 50% से कम भाग पर विचार किया है। मेसर्ज जीएसीएल एक आयातक होने के नाते अयोग्य पात्र है और उनके उत्पादन के बहिष्करण पर सहभागी उत्पादकों का भाग घरेलू उत्पादन का 28% बनता है। इसके अतिरिक्त यदि ऐसी कंपनियों के उत्पादन को बहिष्कृत किया जाता है, जो क्लोरीन के एक संयुक्त उत्पाद मानती है, तो सहभागी कंपनियों का अंशदान घरेलू उत्पादन का 36% बनेगा, जिसे तुच्छ नहीं माना जा सकता है।
- (ङ) याचिकादाता कंपनियों ने ऐसा दावा नहीं किया है कि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है और पाटन-रोधी शुल्क को बढ़ाए जाने का दावा क्षति के खतरे/संभावना पर आधारित है। इसलिए निरंतर क्षति का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग का दायरा गौण और कम महत्वपूर्ण हो जाता है।

### प्रतिवादी हितवद्ध पक्षकारों के विचार

19. घरेलू उद्योग और उसके आधार के बारे में प्रतिवादी पक्षकारों के विचारों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:-

- (क) चूंकि भारतीय उत्पादन में याचिकादाता कंपनियों का हिस्सा 25.06% मात्र बनता है, उनका उत्पादन, घरेलू उद्योग के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रमुख भाग नहीं बनता है। विगत जांच में घरेलू उत्पादन में याचिकादाता कंपनियों का हिस्सा 25% से अधिक बनता था। ईसी-फास्टनर्स के मामले में अपील निकाय ने घरेलू उद्योग बनने के लिए प्रमुख भाग के रूप में 27% को नहीं माना था।
- (ख) यहां तक कि एमटीआर में भी जब याचिकादाता ने 33% बनने के लिए उत्पादकों के आंकड़े प्रस्तुत किए थे, तब प्राधिकारी ने और उत्पादकों के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कहा था ताकि आधार को 49.8% तक लाया जा सके।
- (ग) याचिकादाताओं की सूची के अनुसार ग्रासीम, गंजम एक सहभागी उत्पादक है, जबकि याचिकादाता कंपनियों के आधार के प्रकटन करने वाली याचिका में ग्रासीम, गंजम के स्थान पर डीसीएम, झगाडिया उल्लिखित किया गया है। इस प्रकार 25% का दावा विश्वसनीय सूचना से समर्थित नहीं है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

20. जांच की कार्यवाही के दौरान याचिकादाता के आधार के संबंध में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विभिन्न निवेदनों की जांच और उनका निदान, पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार किया गया है।

21. वर्तमान जांच के लिए घरेलू उद्योग की ओर से मेसर्ज अलकाली मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था। यह नोट किया जाता है कि याचिकादाता कंपनियों नामतः मेसर्ज डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, मेसर्ज ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेसर्ज एसआईईएल, केमिकल कॉम्पलेक्स का उत्पादन, घरेलू उद्योग के उत्पादन का 25.19% बनता है। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया जाता है कि मेसर्ज गुजरा अल्कालीज और केमिकल लिमिटेड (जीएसीएल) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रही है और इसलिए वह घरेलू उद्योग के रूप में अयोग्य है तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का परिकलन करने के लिए उसके उत्पादन को शामिल नहीं किया जाएगा। यह भी नोट किया जाता है कि सहभागी कंपनियों का उत्पादन अत्यधिक है और इस प्रकार याचिकादाता कंपनियां पाटन-रोधी नियमावली में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनती हैं और पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत घरेलू उद्योग के आधार की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। प्राधिकारी ने याचिकादाता के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया है कि क्लोरीन को संयुक्त उत्पाद मानने वाली कंपनियों के उत्पादन को याचिकादाता कंपनियों के घरेलू उद्योग के आधार को निर्धारित करने के लिए बहिष्कृत किया जाए।

22. मेसर्ज डीसीएम, झगाडिया के मामले के संबंध में निवेदन है कि याचिका के एक विवरण में याचिकादाता ने यह स्पष्ट किया है कि यह टंकण की गलती है तथा मेसर्ज ग्रासीम गंजम ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और न कि मेसर्ज डीसीएम, झगाडिया ने।

23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तथा जांच करने के बाद प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक उद्योग आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है और वह पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनता है।

#### गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

##### घरेलू उद्योग के विचार

24. विदेशी उत्पादक/निर्यातक ने दावा किया है कि अत्यधिक गोपनीयता रखी गई है जिसके कारण वह प्रस्तुत उत्तरों के संबंध में सार्थक टिप्पणियां देने में असमर्थ है। अन्य बातों के साथ-साथ वह घरेलू विक्रयों, विक्री कीमत के ढांचे से संबंधित सूचीबद्ध आंकड़े, क्षमता, उत्पादन की लागत के सूचीबद्ध आंकड़े और प्रयुक्त किए गए कच्चे माल के ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

##### प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

25. प्राधिकारी ने गोपनीयता के लिए उनके अनुरोधों के बारे में पहले से स्वयं की संतुष्टि कर ली है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के सुस्थापित पद्धति के आधार पर गोपनीयता रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन के लिए अनुरोध या तो अनुचित थे अथवा बिना सोचे समझे थे।

26. घरेलू उद्योग ने याचिका के अनुबंध 6.2 से 6.6 में उत्पादन की निजी लागत के बारे में पूर्णतया गोपनीयता का दावा किया है और उसने उसका कोई संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। वास्तव में घरेलू उद्योग ने विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि ऐसी सूचना व्यवसाय के स्वामित्व संबंधी सूचना है और इसका संक्षिप्त विवरण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है।

##### प्राधिकारी द्वारा जांच

27. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है।

#### छ. विविध मुद्दे

##### घरेलू उद्योग के विचार

28. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के उत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) जिस अवधि के लिए शुल्क लगाया गया है, यह निर्धारण करने के लिए अप्रासंगिक है कि क्या शुल्कों को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। विधि में शुल्कों को बढ़ाए जाने का प्रावधान है, यदि ऐसे शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा पाटन या क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यहां तक कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्राजील और यूरोपीय यूनियन जैसे अन्य देशों के पद्धति के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के आयात नहीं होने की स्थिति में भी शुल्कों को 15 वर्ष से भी अधिक अवधि तक लागू किया जा सकता है।
- (ख) इस तर्क के संबंध में कि 13 देशों में से 9 देशों जिनके खिलाफ पहले पाटन-रोधी शुल्क लग रहा था, शुल्कों को समाप्त कर दिया गया है, यह तर्क दिया गया था कि यह तथ्य स्वतः यह सिद्ध करता है कि केवल उन्हीं मामलों में शुल्क बढ़ाया गया है, जिनमें शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन अथवा क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- (ग) प्राधिकारी ने याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत विधिवत अधिप्रमाणित आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बाद जांच शुरू की है और इस प्रकार इस तर्क में कोई बल नहीं है कि जांच शुरू नहीं की जानी चाहिए थी।

##### प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

29. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अन्य विभिन्न निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) शुल्क 17 वर्ष की अवधि से लागू हैं। घरेलू उद्योग को वर्ष 2000 से पाटन-रोधी शुल्कों से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ है और आगे कोई संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- (ख) प्रारंभ में वर्ष 2000 में 13 देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लागू किए गए थे। इन 13 देशों में से 9 देशों पर शुल्क पहले से ही हटा दिए गए हैं और बाकी संबद्ध देशों पर से भी इन्हें हटा दिया जाना चाहिए।



- (ग) याचिकादाता द्वारा प्रदत्त सऊदी अरब से तृतीय देश के निर्यात से संबंधित आंकड़े अवश्विसनीय हैं क्योंकि इनके स्रोत की सूचना प्रदान नहीं की गई है।
- (घ) केसोराम रेयन के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास करते हुए पक्षकारों का यह आग्रह है कि प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करें। प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वे स्वयं इस तथ्य से संतुष्ट हों कि क्या प्राप्त हुआ आवेदन-पत्र विधिवत् अधिप्रमाणित है।
- (ङ) याचिकादाता द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र में वर्ष 2016-17 की जांच की अवधि मानने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि जांच की शुरुआत, अप्रैल, 2016 से जून, 2017 तक की जांच अवधि मान कर शुरू की गई है। इस प्रकार पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 का उल्लंघन किया गया है क्योंकि जांच की पूरी अवधि के लिए आंकड़ों की वास्तविक रूप से जांच किए बिना जांच शुरू की गई है।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

30. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए तथा निदान किए गए विभिन्न निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) 17 वर्ष की अवधि के बाद भी शुल्क को जारी रखे जाने के बारे में प्राधिकारी यह पाते हैं कि विगत में शुल्कों को केवल इसलिए आगे बढ़ाया गया था कि जांच के बाद ऐसा पाया गया था कि शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन अथवा क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यह तथ्य कि 13 देशों में से 9 देशों पर शुल्कों को हटा दिया गया है, जिन पर ये शुल्क लागू थे और पांच में से तीन देशों जिनके खिलाफ वर्तमान जांच मूल रूप से शुरू की गई है, को बहिष्कृत कर दिया गया है, स्वतः यह दर्शाता है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोध पर कोई शुल्क नहीं बढ़ाया है और यह माना है कि यदि एक विशेष देश पर शुल्कों को जारी नहीं रखा जाता है, तो क्या पाटन अथवा क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- (ख) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों की यथातथ्यता की जांच की ही और उनकी पर्याप्तता और सत्यता की संपुष्टि होने के बाद ही उन पर विचार किया है।
- (ग) प्राधिकारी ने एक विधिवत् अधिप्रमाणित याचिका प्राप्त होने पर पाटन अथवा क्षति के निरंतर जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने की आवश्यकता के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की है। प्राधिकारी ने ऐसी जांच की शुरुआत, एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जांच करने के विचार से नहीं की है।
- (घ) जांच शुरू करने के समय जांच की अवधि में परिवर्तन किए जाने के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली में ऐसी आवश्यकता निहित नहीं है कि जांच की जाने वाली जांच की अवधि वही हो जो कि दायर की गई याचिका में जांच अवधि उल्लिखित की गई हो। प्राधिकारी जांच शुरू करने से पहले प्रथम दृष्टया इस तथ्य से स्वयं संतुष्ट थे कि पाटन अथवा क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने की आवश्यकता है। तथापि, प्राधिकारी ने इस पर उपयुक्त रूप से विचार किया है कि पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए हाल ही की अवधि को अपनाया जाए। प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई क्रिया-विधि, इस संबंध में प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के समनुरूप है। इस संबंध में यह भी नोट किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा जांच के लिए नियम 5 लागू नहीं होता है और जांच की शुरुआत, नियम 23 द्वारा अधिश्रासित होती है।

#### ज. कार्य-प्रणाली और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

31. प्राधिकारी ने निर्यातक की प्रश्नावलियां संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों को भेजी थीं और उनको सलाह दी थी कि वे निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से सूचना प्रदान करें। सऊदी अरब में मेसर्ज सऊदी पेट्रोकेमिकल कंपनी (एसएडीएफ) नामक केवल एक कंपनी और उसके संबंधित निर्यातक, मेसर्ज सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज (एसएबीआईसी) ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं। तथापि, सहभागी निर्यातक ने सूचित किया है कि जांच की अवधि के दौरान कंपनी ने कोई निर्यात नहीं किया है।

#### घरेलू उद्योग के विचार

32. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) सहभागी उत्पादक और निर्यातक ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटन से मनाही नहीं की है। यदि मेसर्ज आईएचएस केमिकल की रिपोर्टों के अनुसार आंकड़ों पर विचार किया जाता है, तो यह देखा जाएगा कि पाटन मार्जिन ने केवल सकारात्मक है, बल्कि अत्यधिक भी है।

- (ख) यदि दिनांक 28 फरवरी, 2018 के नोटिस संख्या 5/2018 द्वारा जारी की गई प्रश्नावलियों के अनुसार अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता होती है, तो उसे मंगाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी सूचना सतत जांच के प्रयोजनार्थ भी प्रासंगिक है।
- (ग) चूंकि निर्यातक मेसर्स शैल ट्रेडिंग मिडल ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड (एसआईएमई) ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए एसएडीएफ नामक उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और उसे विशिष्ट पृथक मार्जिन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- (घ) जबकि एसएबीआईसी और एसएडीएफ ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने भारत को कोई निर्यात नहीं किया है, सऊदी अरब से किसी भी अन्य निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमरीका से भी किसी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। इस प्रकार ऐसे देश के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत ग्लॉबल क्लोर अल्काली रिपोर्ट (आईएचएस केमिकल) के अनुसार बिक्री कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।
- (ङ) निर्यात कीमत का निर्धारण, डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए और बेहतर प्राक्कलनों के अनुसार समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्ययों और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजन किया जाना चाहिए।
- (च) प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के अनुसार निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए निर्यातक की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ को समायोजित किया जाना चाहिए।
- (छ) इस दलील के प्रत्युत्तर में कि जांच की अवधि के पहले तीन महीनों में कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए, यह तर्क दिया गया था कि प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में पाटन और क्षति मार्जिन का माह-वार-माह का विश्लेषण नहीं किया है और इस प्रकार यह तथ्य अप्रासंगिक है कि जांच की अवधि के केवल कुछ समय में आयात हुए हैं।
- (ज) इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया था कि पूर्व जांच में निर्यातक ने भारित औसत आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। इसके अतिरिक्त पूर्व जांच में व्यापार के स्तर में किसी भी अंतर का दावा नहीं किया गया है। इस प्रकार वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के तरीके में परिवर्तन किए जाने का कोई कारण नहीं है।
- (झ) निर्यातक के इस दावे के प्रत्युत्तर में कि एसटीएमई की निर्यातों में कोई व्यवसायिक रुचि नहीं है और इसलिए उसने भाग नहीं लिया है, यह तर्क दिया गया था कि इस संबंध में उत्पादक का वर्तमान स्वामित्व अप्रासंगिक है। जब तक निर्यातक निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं कर देता तब तक उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- (ञ) उद्योग के अनुभव और बाजार सूचना के आधार पर निर्यात कीमत के समायोजनों का दावा किया गया है।
- (ट) कारखाना-गत स्तर पर कीमत निर्धारित करने के लिए याचिकादाता ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में सूचित सीयूआईएफ कीमत में समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्ययों और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजन किया है। चूंकि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने वाले किसी भी निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी की सामान्य पद्धति को ध्यान में रखते हुए बेहतर प्राक्कलनों के अनुसार निर्यात कीमत में समायोजन किया जाए।
- (ठ) कारखाना-गत स्तर पर व्यापार के समान स्तर पर निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना की जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए निर्यातक के एसएंडजी व्ययों और लाभ को भी कम किया जाए।

#### प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

33. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) जांच अवधि के दौरान एसएडीएफ ने एसटीएमई के माध्यम से भारत को कुछ निर्यात किए हैं। तथापि, एसएडीएफ और एसटीएमई के बीच विपणन करार 30 सितंबर, 2017 तक वैध था और इस प्रकार उसका संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों में कोई व्यवसायिक रुचि नहीं है और उसने वर्तमान जांच में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- (ख) याचिकादाता ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए किए गए समायोजनों का आधार बने और इस प्रकार दायर याचिका के आधार पर यह जांच शुरू नहीं की जानी चाहिए थी।
- (ग) जांच अवधि के लिए क्लोर अल्काली की रिपोर्ट के अनुसार कीमत ली गई है, जबकि निर्यात, पहले तीन महीनों में अर्थात् अप्रैल से जून, 2016 तक किए गए हैं। इस प्रकार ऐसी कोई उचित तुलना नहीं की गई है, जैसा कि अनुबंध-1 के पैरा 6 में अपेक्षित है।

- (घ) कारखाना-गत स्तर पर कीमत निर्धारित करने के लिए सामान्य मूल्य को समायोजित किया जाना चाहिए। कारखाना-गत स्तर पर सामान्य मूल्य और कारखाना-गत स्तर पर निर्यात कीमत के बीच तुलना से यह पता चलेगा कि सऊदी अरब से कोई पाटन नहीं हुआ है।
- (ङ) प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का उपयोग, सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का परिकलन करने के लिए किया जाना चाहिए।
- (च) घरेलू उद्योग के आरोप के प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया गया था कि निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में पाटन मार्जिन का दावा करने के लिए निर्यातक के पास कोई कारण नहीं है। फिर भी निर्यातकों ने अपने निवेदनों में विशेष रूप से यह दावा किया है कि कोई पाटन नहीं हुआ है।
- (छ) अतिरिक्त सूचना की आवश्यकताओं के संबंध में यह निवेदन किया गया था कि ट्रेड नोटिस संख्या 5/2018 केवल ऐसी जांच पर लागू होता था, जिसे 28 फरवरी, 2018 के बाद शुरू किया गया था।
- (ज) घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि निर्यातक की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और लाभ को कम किया जाना चाहिए, यह आग्रह किया गया था कि घरेलू उद्योग ने पहले से ही कमीशन के लिए 3% का समायोजन करने का दावा किया है, जो कि ऐसे व्ययों और लाभ को शामिल करने के लिए पर्याप्त होगा।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

34. वर्तमान जांच में निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर, मेसर्स सऊदी अरब पेट्रोकेमिकल कंपनी (एसएडीएफ) (उत्पादक) ने अपने संबंधित निर्यातक, मेसर्स सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज (एसएबीआईसी) के साथ मिलकर प्रस्तुत किए हैं। उनके उत्तर के अनुसार उन्होंने \*\*\*मी.टन निर्यात किए जाने की घोषणा की है, जो कि डीजीसीआईएंडएस के कास्टिक सोडा लाई के 32,097 मी.टन निर्यात के आंकड़ों से प्राप्त मात्रा से बहुत कम है। इसकी जांच की गई और यह पाया गया है कि ऐसा अंतर इस तथ्य के कारण है कि निर्यातक ने जांच अवधि से पहले वस्तुओं की बीजक बनाई थी। इसलिए उसे परिशिष्ट-2 में घोषित नहीं किया था। तथापि, वस्तुएं जांच अवधि के दौरान भारत में पहुंची थीं और इसलिए उन्हें डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में शामिल किया गया है।

35. यह देखा गया है कि एसएडीएफ विचाराधीन उत्पाद की उत्पादक कंपनी है और उसने अपने संबंधित निर्यातक को भारत में निर्यात करने के लिए वस्तुओं को बेचा था। मेसर्स शैल ट्रेडिंग मिडल ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड (एसटीएमई) द्वारा उक्त मदों के निर्यात भारत को किए गए थे, जिसने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। उत्पादक ने यह बताया है कि एसटीएमई ने अपने शेयरों को बेच दिया है और अब वह एसएडीएफ की सहभागी नहीं है। इसके अतिरिक्त उत्पादक की अन्य संबंधित कंपनी, एसएबीआईसी ने यह दावा किया है कि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद की निर्यातक कंपनी है। तथापि, कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को कोई निर्यात नहीं किया है। भारत में जिस कीमत पर वस्तुओं को निर्यात किया गया है वह कीमत तथा निर्यात कीमत का निर्धारण करने से संबद्ध अनेक अन्य सूचनाएं एसटीएमई के पास हैं, जिसने प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि चूंकि एसटीएमई ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, एसएडीएफ - एसआईएमई को विशिष्ट पृथक मार्जिन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त चूंकि एसएबीआईसी ने जांच अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, वह निर्यातक के पद का दावा नहीं कर सकती है। इस प्रकार प्राधिकारी एसएडीएफ - एसआईएमई अथवा एसएडीएफ - एसएबीआईसी के लिए विशिष्ट पृथक पाटन मार्जिन का निर्धारण करने में असमर्थ हैं। प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि सऊदी अरब से आयातों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण, बेहतर उपलब्ध सूचना के आधार पर किया जाए।

36. प्राधिकारी प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का कोई महत्व नहीं पाते हैं कि पहले तीन महीनों के लिए सामान्य मूल्य को ध्यान में रखते हुए पाटन मार्जिन परिकलित किया जाए क्योंकि संबद्ध वस्तुओं से संबंधित विगत किसी भी जांच में इस तथ्य के बावजूद कि अनेक जांच में समस्त जांच अवधि के दौरान आयात नहीं हुए थे, मास-वार विश्लेषण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सहभागी उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की पृथक लागत का कोई दावा नहीं किया है। इसलिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है।

#### I. सामान्य मूल्य

37. प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार बेहतर उपलब्ध सूचना के आधार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाए। तदनुसार, अत्यधिक कुशल घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य संरचित किया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए उत्पादन की लागत के 5% के उचित लाभ को भी जोड़ा गया है।

II. निर्यात कीमत

38. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार बेहतर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों के संबंध में निर्यात कीमत निर्धारित की है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आंकड़ों को अपनाया है और भारत में विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों को ध्यान में रखते हुए निर्यात कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की कारखाना-गत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए निर्यात कीमत में समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्ययों, अंतर्देशीय भाड़े के व्ययों और बैंक प्रभारों को समायोजित किया गया है।

III. पाटन मार्जिन

39. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन तथा व्यापार दो रूपों में किया जाता है अर्थात् लाइ एवं फ्लैक। तथापि क्योंकि आयात केवल लाइ रूप में किया जाता है, इसलिए तदनुसार पाटन मार्जिन की गणना करने हेतु लाइ के लिए सामान्य मूल्य की तुलना निवल निर्यात मूल्य से की गई है। आंकड़ों के विश्लेषण के बाद पाटन मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए अनुसार निर्धारित किया गया है।

क्र. सं.	निर्यात का देश	निर्धारित सामान्य मूल्य	निवल निर्यात मूल्य	पाटन मार्जिन		
		अमेरिकी \$/एमटी	अमेरिकी \$/एमटी	अमेरिकी \$/एमटी	%	श्रेणी
1	सऊदी अरब	***	***	***	***	20-30
2	यूएसए	***	***	***	***	105-115

40. संबद्ध देशों के संबंध में इस प्रकार निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन अन्वेषणाधीन अवधि के लिए सकारात्मक है।

I. क्षति के निर्धारण की पद्धतिघरेलू उद्योग के विचार

41. घरेलू उद्योग ने क्षति तथा कारणात्मक संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की है:

- क. आधार वर्ष 2013-14 की तुलना में अन्वेषणाधीन अवधि के दौरान आयात में गिरावट आई है परंतु जब वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्षति की अवधि के लिए जांच की गई तो वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में और वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में आयात में वृद्धि दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास आवश्यकता से अधिक क्षमता है जिसे भारत में बाजार पर नियंत्रण करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।
- ख. जहां उत्पादन अथवा उपभोग की तुलना में आयात अधिक उल्लेखनीय नहीं हैं, यह केवल लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव है। शुल्क समाप्त होने की स्थिति में आयात में वृद्धि होने की संभावना है।
- ग. सऊदी अरब से आयात की मात्रा में केवल एसटीएमई और एसएबीआईसी के बीच समझौता समाप्त होने के कारण कमी आई है। जहां एसटीएमई द्वारा किए जाने वाले निर्यात पर शून्य शुल्क था वहीं एसएबीआईसी द्वारा चालान की गई वस्तुओं पर शुल्क लगाया जा रहा था। इसलिए समझौता समाप्त होने के बाद एसएबीआईसी के पास उत्पाद का निर्यात बंद करने और शुल्क समाप्त होने की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था।
- घ. आयात से घरेलू उद्योग में मूल्यों में गिरावट हो रही है, जो दर्शाता है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को नुकसान उठाना पड़ेगा।
- ङ. यदि घरेलू उद्योग को आयातित वस्तुओं पर आयात किए जाने वाले मूल्य में से शुल्क हटा कर आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है तो इसकी लाभकारिता प्रभावित होगी।
- च. आयातित वस्तुओं का आयात किए जाने वाला मूल्य घरेलू उद्योग के उचित बिक्री मूल्य अथवा नुकसान न पहुंचाने वाले मूल्य से कम है।
- छ. जहां घरेलू उद्योग का उत्पादन तथा क्षमताएँ बढ़ी हैं वहीं उत्पादन में वृद्धि सृजित क्षमताओं की तुलना में कम है।
- ज. जहां वर्ष 2015-16 तक घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा बढ़ रहा था वहीं अन्वेषणाधीन अवधि में यह घटा है।
- झ. क्षति की अवधि में वर्ष 2015-16 तक घरेलू उद्योग का औसत स्टॉक बढ़ा है, तथापि अन्वेषणाधीन अवधि में यह घटा है।
- ञ. लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर आय में वृद्धि हुई है।

- ट. घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट नहीं आई तो इसका एकमात्र कारण था कि लागू शुल्क के कारण आयात की मात्रा कम थी।
- ठ. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान मूल्य में कमी अथवा गिरावट केवल नए सिरे से किए गए अन्वेषण के मामले में अथवा जहां लगातार क्षति हो रही है उस मामले में संगत है।
- ड. निर्यातक का यह तर्क कि क्षति का मार्जिन पहली तीन अवधि में क्षति की अवधि के अतिरिक्त अन्य अवधि के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण था चूंकि पूर्व में जब मूल्यों में अंतर आया था तब ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था।
- ढ. बाद में समीक्षा अन्वेषण के मामले में कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- ण. चूंकि घरेलू उद्योग ने केवल नुकसान के खतरे अथवा संभावना का दावा किया है, इसलिए विपरीत हितों वाले पक्षों द्वारा रेखांकित किए गए जल की कमी, कच्चे माल की कमी तथा अन्य घटक संगत नहीं हैं।
- त. जब घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति का दावा नहीं किया है तो स्पष्ट रूप से पाटन और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं हो सकता। कारणात्मक संबंध केवल यह निर्धारित करने के लिए संगत होगा कि क्या शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचने की संभावना है।
- थ. इस संबंध में किए गए उल्लेख का उत्तर देते हुए यह तर्क दिया गया था कि संबद्ध आयात की तुलना में अन्य देशों से आयात बहुत अधिक मूल्य पर होते हैं। इस प्रकार इनसे घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुआ।

#### विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

42. क्षति तथा कारणात्मक संबंध के संदर्भ में विपरीत हितों वाले पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियाँ:
- क. सऊदी अरब से कुल आयात में निरपेक्ष रूप से और कुल आयात तथा घरेलू उत्पादन की तुलना में गिरावट आई है।
- ख. अधिकतर आयात उन देशों से किया गया है जिन पर से शुल्क हटा लिया गया है।
- ग. मूल्य में कोई कमी अथवा गिरावट नहीं आई है चूंकि घरेलू उद्योग लागत तथा माल उतारने तक के मूल्य में गिरावट के बावजूद अपने बिक्री मूल्य को बढ़ाने में सक्षम रहा है।
- घ. वर्ष 2015-16 की तुलना में जांच की अवधि में मूल्य में कमी किए जाने के बावजूद इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ में वृद्धि हुई।
- ड. यद्यपि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2013-14 और 2015-16 के लिए मूल्य में कमी की गणना नहीं की है, परंतु संबद्ध देशों के लिए समग्र रूप से मूल्य में सकारात्मक कमी की गणना की गई है। स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग द्वारा की गई गणना पूर्णतया वृष्टिपूर्ण है।
- च. चूंकि आयात केवल पहले तीन माह के दौरान हुआ है, अर्थात् अप्रैल से जून, 2016 तक, इसलिए इस अवधि हेतु क्षति रहित कीमत पर बिक्री निर्धारित की जानी चाहिए और इसके और आयात के बीच उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए इसकी आयातित वस्तुओं के पहुंच मूल्य से तुलना की जानी चाहिए।
- छ. कम कीमत पर बिक्री के बावजूद घरेलू उद्योग रिकॉर्ड लाभ अर्जित करने में सफल रहा है जो कि करणीय संबंध में गंभीर अंतर को दर्शाता है।
- ज. आयात में वृद्धि के बावजूद उत्पादन, क्षमता, क्षमता के उपयोग, बिक्री, सूचियों, लाभ तथा निवेशित पूंजी पर प्रतिफल सहित घरेलू उद्योग के सभी आर्थिक प्राचलों में क्षति की अवधि में सुधार देखा गया है। इस प्रकार शुल्क को जारी रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- झ. जब घरेलू उद्योग ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इसे क्षति की अवधि के दौरान घाटा नहीं हुआ है तो यह दावा असंगत है कि पिछले वर्ष की तुलना में जांचाधीन अवधि में कुछ गिरावट आई है।
- ञ. क्षति के मार्जिन की गणना सभी लेन-देन को ध्यान में रखते हुए भारित औसत आधार पर की जानी चाहिए और न कि उन लेन-देन के आधार पर जो क्षति न पहुँचने के मूल्य से कम हैं जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है।
- ट. यदि शुल्क लगाए जाने के 14 वर्ष बाद भी घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँच रहा है तो यह स्पष्ट है कि यह नुकसान बाहरी घटकों के परिणामस्वरूप है।

- ठ. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने उल्लेख किया है कि इसे तमिलनाडु में पानी की कमी और साह्यपुरम में श्रमिकों की समस्याओं के कारण संबद्ध वस्तुओं के कारोबार में गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप एक संयंत्र बंद करना पड़ा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वर्ष 2016-17 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि इसे विमुद्रीकरण के कारण नुकसान हुआ जबकि एसआईईएल ने स्वीकार किया है कि उन्हें होने वाले नुकसान का कारण कच्चे माल की उच्च लागत है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को नुकसान विषयगत आयात के कारण नहीं हुआ है।
- ड. एसआईईएल ने रिपोर्ट किया है कि आयात में कमी के कारण कास्टिक सोडा की कमी हो गई थी। यदि आयात घरेलू उद्योग को इसकी बिक्री बढ़ाने से रोक रहे होते तो शुल्क लागू होने के बाद यह अपनी बिक्री की मात्रा बढ़ाने में सफल होना चाहिए था।
- ढ. संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख उपभोक्ता, अर्थात् एल्यूमिनियम उद्योग, पूर्वी तट पर स्थित है वहीं याचिकाकर्ता उद्योग पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट से वस्तुओं को ले जाने की उच्च लागत के कारण आयात की मांग बढ़ जाती है।
- ण. याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े असंगत हैं और त्रुटिपूर्ण हैं। याचिका में प्रस्तुत की गई मांग और अनुलग्नक में दी गई मांग मेल नहीं खाती। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने निवेश पर प्रतिफल के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- त. घरेलू उद्योग ने याचिका में यह दावा किया था कि सऊदी अरब, ईरान, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाले आयात से नुकसान होने की संभावना है परंतु अब यह दावा नहीं कर सकता कि केवल सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्षति तथा पाटन के बीच कारण संबंध की परिकल्पना करना तर्कपूर्ण है।
- थ. प्राधिकारी ने पूर्व में कुछ बाद की समीक्षा वाले मामलों में यह निष्कर्ष दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति छोड़े गए आयात के कारण नहीं हुई बल्कि अन्य घटकों के कारण हुआ था और इसलिए शुल्क को जारी नहीं रखा गया। इसी प्रकार वर्तमान मामले में भी प्राधिकारी को यह निर्धारण करना चाहिए कि यदि कथित पाटन तथा घरेलू उद्योग को कथित नुकसान के बीच कोई कारण संबंध है, यदि कोई हो।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

43. इसके तहत प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति के विश्लेषण में स्वयमेव हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया है। तथापि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई विशिष्ट टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी की गई है:

- क. क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की पर्याप्तता तथा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए यथोचित रूप से सत्यापन करने के बाद इन पर विचार किया है।
- ख. एनआईपी का निर्धारण याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के यथोचित सत्यापन के बाद इन आंकड़ों के आधार पर किया गया था। यह नोट किया गया कि घरेलू उद्योग क्लोरीन तथा हाइड्रोजन को सह-उत्पाद मानता था। क्लोरीन गैस को व्यापारिक बिक्री के लिए द्रव रूप में बदला जाता है अथवा अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए गैस रूप में भंडारित करके इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकतर इकाइयों के लिए क्लोरीन कास्टिक सोडा के उत्पादन में बाधा है, कभी-कभी उन्हें क्लोरीन की पर्याप्त भंडारण क्षमता/बिक्री न होने के कारण संयंत्र को बंद करना पड़ता है। अधिकतर मामलों में क्लोरीन को घाटे में बेचा जाता है अथवा उन्हें क्रेता को आपूर्ति लेने के लिए माल-भाड़ा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। घरेलू उद्योग ने क्लोरीन तथा हाइड्रोजन संयंत्र के लिए प्रयुक्त स्थायी संपत्तियों पर वापसी का दावा किया चूंकि ये दोनों कास्टिक सोडा के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
- ग. क्षति की अवधि अथवा जांचाधीन अवधि में विद्यमान घटक जैसे पानी की कमी, कच्चे माल की कमी, विमुद्रीकरण आदि केवल उस स्थिति में संगत हैं जहां घरेलू उद्योग के निष्पादन में कोई गिरावट आई है। जब घरेलू उद्योग ने छोड़ी गई वस्तुओं के आयात के कारण अपने निष्पादन में किसी वास्तविक गिरावट का दावा नहीं किया है तो इस तथ्य कि पानी की कमी हो गई अथवा संयंत्र को किसी अन्य कारण से बंद करना पड़ा, अथवा घरेलू उद्योग को किन्हीं अन्य कारणों से नुकसान हुआ, का यह अर्थ नहीं है कि कारण संबंध में कोई अंतराल आया है। इसी प्रकार जब घरेलू उद्योग अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने में सफल रहा है तो यह नहीं कहा जा सकता कि घरेलू उद्योग को प्रतिकूल भौगोलिक स्थितियों के कारण नुकसान हुआ। यह केवल उन मामलों में है जहां घरेलू उद्योग को अन्वेषणाधीन अवधि में नुकसान हुआ है परंतु यह नुकसान अन्य घटकों के कारण हुआ है, जहां ये सभी घटक अन्वेषण के लिए संगत हो जाते हैं। वर्तमान मामला पाटनरोधी शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग को नुकसान के खतरे/संभावना पर विचार करने का है।

घ. जहां तक पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि अन्वेषणाधीन अवधि में मूल्य में प्रतिस्पर्धात्मक गिरावट में कमी आने के बावजूद लाभ बढ़ा है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मूल्य में सकारात्मक प्रतिस्पर्धात्मक गिरावट तथा बिक्री में गिरावट केवल यह प्रदर्शित करती है कि आयातित वस्तुओं का माल उतारे जाने तक का मूल्य बिक्री मूल्य तथा नुकसान न होने वाले मूल्य से कम है, जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग को नुकसान न होने वाले मूल्य से कम मूल्य पर उत्पाद की बिक्री करनी होगी और पाटनरोधी शुल्क हटाने की स्थिति में इसकी लाभकारिता में कमी आएगी।

44. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

45. पाटनरोधी नियमों के नियम 23 में यह प्रावधान है कि समीक्षा के मामले में नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग के निष्पादन से यह प्रदर्शित होता है कि इसे वर्तमान नुकसान अवधि के दौरान नुकसान नहीं हुआ है तो प्राधिकरण यह निर्धारण करेगा कि क्या वर्तमान शुल्क को हटाने से घरेलू उद्योग को पुनः नुकसान होने की संभावना है।

46. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए विभिन्न दस्तावेजों पर विचार करते हुए प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयात के कारण पाटन तथा क्षति के संभावित पहलुओं की जांच करने के लिए कार्रवाई करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। इस उद्देश्य से प्राधिकारी ने उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों पर विचार किया है जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभकारिता, निवल बिक्री से आय और नियमों के अनुलग्नक- II के अनुसार पाटन की मात्रा तथा मार्जिन।

#### I. क्षति का संचयी आकलन

47. पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक II(iii) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयातों का लगातार पाटनरोधी अन्वेषण किया जा रहा है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेंगे यदि यह निर्धारित करता है कि:-

क. प्रत्येक देश/क्षेत्र से आयात के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त प्रतिशत से दो प्रतिशत से अधिक हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तुओं के आयात का तीन प्रतिशत हो अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम हो, आयात संचयी रूप से समान वस्तुओं के आयात के सात प्रतिशत से अधिक हो, और;

ख. आयात के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु और इसके समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में उचित है।

48. वर्तमान मामले में प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है; प्रत्येक संबद्ध देश से छोड़ी गई वस्तुओं के आयात की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है; और संबद्ध देशों से निर्यात प्रत्यक्ष रूप से भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के बीच और इनके साथ प्रतिस्पर्धा करता है। छोड़ी गई वस्तुओं के आयात के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों तथा समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित है। इसलिए प्राधिकारी संबद्ध देशों से छोड़ी गई वस्तुओं के आयात के प्रभाव का संचयी आकलन करना उचित समझता है।

#### II. कुल मांग और बाजार हिस्सा

49. संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उपभोग/मांग के आकलन के उद्देश्य से भारत में कुल आयात में घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री की मात्रा को जोड़ा गया है और इसका सार नीचे दिया गया है। कास्टिक सोडा का निर्माण दो रूप में किया जाता है, लाइ और फ्लेक और इन दोनों ही रूपों को मूल तथा वर्तमान अन्वेषण में विषयगत वस्तुओं में शामिल किया गया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई	पीओआई (ए)
क	संबद्ध वस्तुओं की मात्रा						
1	यांत्रिकाकर्ता कंपनियाँ	एमटी	***	***	***	***	***
1क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	146	184	147
2	अन्य भारतीय उत्पादक	एमटी	***	***	***	***	***
2क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	101	135	108
3	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	52,081	13,151	25,036	49,065	39,252
4	आयात – अन्य देश जिन पर शुल्क लागू है	एमटी	100,043	180,974	89,711	78,883	63,106
5	आयात – अन्य देश	एमटी	152,350	212,532	360,140	378,869	303,096
6	कुल मांग	एमटी	2,756,353	3,048,528	3,176,062	4,047,653	3,238,122
ख	मांग में बाजार हिस्सा						
7	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
7क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	129	129	129
8	अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***	***
8क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	88	92	92
9	आयात – संबद्ध देश	%	2	0	1	1	1
10	आयात – अन्य देश जिन पर शुल्क लागू है	%	4	6	3	2	2
11	आयात – अन्य देश	%	6	7	11	9	9

50. यह देखा गया है कि क्षति की अवधि में और जांचाधीन अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। क्षति की पूर्ण अवधि और जांचाधीन अवधि (ए) के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लगातार बढ़ रही है। भारतीय उत्पादकों की बिक्री क्षति की पूर्ण अवधि और जांचाधीन अवधि (ए) के दौरान उल्लेखनीय रही है और लगातार बढ़ी है। संबद्ध देशों से आयात क्षति की पूर्ण अवधि के दौरान घटा है और जांचाधीन अवधि (ए) के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 के दौरान संबद्ध देशों को छोड़ कर जिन देशों पर एडीडी लागू है वहाँ से आयात थोड़ा बढ़ा है परंतु क्षति की शेष अवधि और अन्वेषणाधीन अवधि (ए) के दौरान इसमें लगातार कमी आई है। शेष देशों से आयात क्षति की पूर्ण अवधि के दौरान लगातार बढ़ा है परंतु जांच की अवधि (ए) के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में इसमें थोड़ी कमी आई है।

51. क्षति की पूर्ण अवधि और अन्वेषणाधीन अवधि के दौरान भारत में पीयूसी की कुल मांग में घरेलू उद्योग की बिक्री का बाजार हिस्सा लगभग समान रहा है, तथापि भारत में पीयूसी की कुल मांग में अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री का बाजार हिस्सा यद्यपि थोड़ा कम हुआ है परंतु फिर भी यह उल्लेखनीय रहा है। भारत में विषयगत वस्तुओं की कुल मांग में आयात का बाजार हिस्सा नुकसान की पूर्ण अवधि के दौरान कम रहा है जो कि एडीडी लागू होने के कारण हो सकता है। शेष देश जिन पर एडीडी लागू है और अन्य देशों से आयात का बाजार हिस्सा उल्लेखनीय नहीं है यद्यपि यह संबद्ध देशों से आयात की तुलना में अधिक है।

### III. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

52. पाटित वस्तुओं के आयात की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना है कि क्या निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा उपभोग की तुलना में पाटित वस्तुओं के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस उद्देश्य से प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आयात संबंधी आंकड़ों को आधार बनाया है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

क. आयात की मात्रा, उत्पादन तथा खपत की तुलना में आयात का हिस्सा

53. आयात की मात्रा तथा आयात के हिस्से से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं:



क्र. सं.	विवरण	यूओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई	पीओआई (ए)
1	कुल मांग	एमटी	2,756,3 53	3,048,5 28	3,176,0 62	4,047,6 53	3,238,1 22
2	घरेलू उत्पादन	एमटी	***	***	***	***	***
2क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	110	144	115
3	आयात						
3क	आयात – संबद्ध देश	एमटी	52,081	13,151	25,036	49,065	39,252
3क (i)	सऊदी अरब	एमटी	52,081	13,144	25,036	32,097	25,678
3क (ii)	यूएसए	एमटी	-	7	-	16,968	13,574
3ख	आयात – अन्य देश जिन पर शुल्क लागू है	एमटी	100,043	180,974	89,711	78,883	63,106
3ग	आयात – अन्य देश	एमटी	152,350	212,532	360,140	378,869	303,096
3घ	कुल आयात	एमटी	304,474	406,657	474,887	506,817	405,454
4	कुल आयात के संबंध में आयात में हिस्सा						
4क	आयात – संबद्ध देश	%	17	3	5	10	10
4क (i)	सऊदी अरब	एमटी	52,081	13,144	25,036	32,097	25,678
4क (ii)	यूएसए	एमटी	-	7	-	16,968	13,574
4ख	आयात – जिन देशों पर शुल्क लागू है (संबद्ध देशों को छोड़ कर)	%	33	45	19	16	16
4ग	आयात – अन्य देश	%	50	52	76	75	75
5	निम्न के संबंध में संबद्ध देशों से आयात का हिस्सा						
5क	उत्पादन	%	***	-	***	***	***
5क (i)	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	-	50	50	50
5ख	उपभोग	%	2	0	1	1	1

54. यह देखा गया है कि नुकसान की पूर्ण अवधि और अन्वेषणाधीन अवधि के दौरान भारत में पीयूसी की मांग लगातार बढ़ रही है (वार्षिक अनुमानों के अनुसार जाँची गई), तथापि संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष से 2015-16 तक घटे हैं, यद्यपि जांच की अवधि (ए) के दौरान पिछले वर्ष अर्थात् 2015-16 की तुलना में आयात में वृद्धि हुई है। पीयूसी के कुल आयात में विषयगत देशों से आयात का हिस्सा उल्लेखनीय नहीं है और क्षति की पूर्ण अवधि के दौरान इसमें गिरावट भी आ रही है परंतु जांच की अवधि (ए) के दौरान पिछले वर्षों अर्थात् 2014-15 और 2015-16 की तुलना में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। अन्य देशों से आयात उल्लेखनीय हैं और इनमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में उत्पादन तथा उपभोग की तुलना में आयात का हिस्सा लगभग नगण्य है और इसमें भी गिरावट आ रही है।

#### IV. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

55. कीमतों पर पाटित आयात के कथित प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों के मूल्य की तुलना में मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है, अथवा क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट लाने अथवा मूल्य में संभावित उल्लेखनीय वृद्धि को रोकने के रूप में हुआ है। संबद्ध देशों से कथित रूप से छोड़ी गई वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू उद्योग के मूल्यों पर प्रभाव की मूल्य में तुलनात्मक गिरावट, मूल्य पर कम बिक्री, मूल्य में गिरावट अथवा मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की विषयगत देशों से आयात की माल उतारे जाने तक की लागत से तुलना की गई है।

## क. कीमत कटौती

56. जांच की अवधि के दौरान आयात के माल उतारे जाने तक के मूल्य की भारत में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू बिक्री मूल्य से तुलना करके मूल्य में प्रतिस्पर्धात्मक गिरावट का आकलन किया गया है। इस उद्देश्य से कारखाना मूल्य स्तर पर सभी छूट तथा करों के बाद घरेलू उद्योग के निवल औसत बिक्री मूल्य को आधार बनाया गया है। उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए कास्टिक सोडा का लाइ रूप में बिक्री मूल्य लिया गया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई
1	आयातों की पहुंच कीमत	रुपये/ एमटी	22,804	22,761	24,880	23,371
2	घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति	रुपये/ एमटी	***	***	***	***
2क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	95	99
3	कीमत कटौती	रुपये/ एमटी	***	***	***	***
3क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	7	77
4	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
4क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	7	79
5	कीमत कटौती रेंज	%	10-20	5-15	0-5	5-15

57. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत का मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम है। क्षति की पूर्ण अवधि और जांचाधीन अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री से निवल आय लगातार आयात के पहुंच मूल्य से अधिक है।

## ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

58. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या छोड़ी गई वस्तुओं के आयात से घरेलू मूल्य में कमी अथवा गिरावट आ रही है और क्या ऐसे आयात का प्रभाव मूल्य में उल्लेखनीय कमी लाने अथवा अन्यथा संभावित मूल्य वृद्धि को रोकने के रूप में हुआ है, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में लागत तथा मूल्य में परिवर्तन करने पर विचार किया। इस संबंध में स्थिति नीचे दी गई तालिका के रूप में दर्शाई गई है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2013-14	2014-15	2015-16	पीओआई
क	लाइ के रूप में कास्टिक सोडा					
1	आयातों की पहुंच कीमत	रुपये/ एमटी	22,804	22,761	24,880	23,371
1क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	109	102
2	घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत	रुपये/ एमटी	***	***	***	***
2क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	83	84
3	घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रुपये/ एमटी	***	***	***	***
3क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	95	99
ख	फ्लैक के रूप में कास्टिक सोडा					
4	घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत	रुपये/ एमटी	***	***	***	***
4क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	96	99
5	घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत	रुपये/ एमटी	***	***	***	***
5क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	104	116

59. उपर्युक्त से यह देखा गया है कि वर्ष 2015-16 तक आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई और उसके बाद जांचाधीन अवधि में इसमें गिरावट आई। इसके विपरीत लाइ रूप में कास्टिक सोडा के लिए घरेलू उद्योग का बिक्री मूल्य वर्ष 2015-16 तक घटा है, और जांचाधीन अवधि में लागत में कमी के बावजूद बढ़ा है। इसी प्रकार परत रूप में कास्टिक सोडा के मामले में, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई है, जबकि ऐसी वस्तुओं का बिक्री मूल्य आधार वर्ष की तुलना में थोड़ा कम हुआ है। इसलिए ऑन रिकॉर्ड आंकड़े छोड़ी गई वस्तुओं के आयात के कारण मूल्य में कोई कमी अथवा गिरावट नहीं दर्शाते।

ग. कम कीमत पर बिक्री

60. कम कीमत पर बिक्री की गणना करने के उद्देश्य से पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक-III के अनुसार क्षति रहित कीमत निर्धारित की गई है और इसकी तुलना संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। एक उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए केवल लाइ के रूप में उत्पादित विषयगत वस्तुओं के लिए क्षतिरहित कीमत की गणना की गई है।

देश	पहुंच मूल्य	क्षतिरहित कीमत	कम कीमत पर बिक्री		
	अमेरिकी \$/एमटी	अमेरिकी \$/एमटी	अमेरिकी \$/एमटी	%	श्रेणी
सऊदी अरब	358	***	***	***	10-20
यूएसए	323	***	***	***	20-30

61. क्षतिरहित कीमत की पहुंच मूल्य से तुलना से यह नोट किया गया है कि कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है, और संबद्ध आयात का मूल्य क्षति रहित कीमत से उल्लेखनीय रूप से कम है।

V. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

62. पाटनरोधी नियमों के अनुलग्नक-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे आयात के ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादों पर परिणामी प्रभाव की निष्पक्ष जांच होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादों पर ऐसे आयात के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमों में आगे प्रावधान किया गया है कि घरेलू उद्योग पर छोड़ी गई वस्तुओं के आयात के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, परिणाम, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक अथवा संभावित गिरावट; घरेलू मूल्यों को प्रभावित करने वाले घटकों, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, सूची, रोजगार, पारिश्रमिक, वृद्धि, पूंजीगत निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक तथा संभावित प्रतिकूल प्रभावों सहित उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक घटकों तथा सूचकांकों का एक वस्तुपरक तथा निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल किया जाना चाहिए।

63. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है:

क. नकदी प्रवाह पर लाभ और वास्तविक तथा संभावित प्रभाव

64. घरेलू उद्योग ने कहा है कि प्रवृत्त शुल्कों के साथ, घरेलू उद्योग हानियों की पूर्ववर्ती स्थिति से लाभ प्राप्त करने की स्थिति से लाभ प्राप्त करने की स्थिति में आ गया है। परिणामस्वरूप, ब्याज पूर्व लाभ, नकदी प्रवाह और निवेशों पर आय में भी सुधार हुआ है। हालांकि, उद्योग के निवेशों पर आय संतुलित स्तर पर है।

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	पी ओ आई	पी ओ आई (क)
1	बिक्री की लागत	रु./ मी. टन	***	***	***	***	***
1क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	85	86	86
2	बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	***	***	***	***	***
2क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	100	109	109
3	लाभ/ हानि	रु./ मी. टन	(***)	(***)	***	***	***
3क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(199)	2,915	5,677	5,677
4	लाभ / हानि	रु./ मी. टन	(***)	(***)	***	***	***

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	पी ओ आई	पी ओ आई (क)
4क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(117)	771	1,472	1,840
5	ब्याज पूर्व लाभ	रु./ मी. टन	***	***	***	***	***
5क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	219	350	437
6	नकद लाभ	रु./ मी. टन	***	***	***	***	***
6क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	369	523	653
7	निवेश पर आय	%	***	***	***	***	***
7क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64	179	284	284

65. यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की स्थिति में लाभ दर्शाते हुए लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नकदी प्रवाह और आर ओ आई ने सकारात्मक और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ख. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

66. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग नीचे दी गई सारणी में दर्शाए गए अनुसार है :-

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	पी ओ आई	पी ओ आई (क)
1	क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***
1क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	129	175	140
2	उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***	***
2क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	122	144	185	148
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
3क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	112	106	106
4	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
4क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	145	185	148

67. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त क्षमता उपयोग में भी 2013-14 और 2015-16 के बीच वृद्धि हुई है, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट देखी गई है।

ग. माल सूची

68. निम्नलिखित सारणी में संबद्ध वस्तुओं की माल सूची से संबंधित आंकड़े दर्शाए गए हैं:-

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	पी ओ आई	पी ओ आई (क)
1	अथशेष माल सूची	मी. टन	***	***	***	***	***
2	अंत शेष माल सूची	मी. टन	***	***	***	***	***
3	औसत माल सूची	मी. टन	***	***	***	***	***
3क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	102	84	84

69. उपर्युक्त से, यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत माल सूची स्थिति में सुधार हुआ है घरेलू उद्योग की बेहतर बाजार स्थिति की ओर संकेत करता है।

## घ. रोजगार, वेतन और उत्पादकता

70. निम्नलिखित सारणी में रोजगार, वेतन और उत्पादकता से संबंधित आंकड़े दर्शाए गए हैं :-

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2013-14	2014-15	2015-16	पी ओ आई	पी ओ आई (क)
1	कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***	***
1क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	107	107	107
2	वेतन	रु. लाख	***	***	***	***	***
2क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	137	169	135
3	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मीटन .	***	***	***	***	***
3क	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	135	139	139

71. उपर्युक्त सारणी में यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की वेतन और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि और पी ओ आई (क) के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि बेहतर कार्य कुशलता की ओर संकेत करती है और वेतनों में वृद्धि समय के साथ सामान्य बाजार स्थितियों की प्रगतिकारी स्थिति की प्रतिक्रिया में हो सकती है।

ड. पाटन और पाटन मार्जिन की मात्रा :

72. पाटन की मात्रा उस सीमा का संकेतक है जिस तक पाटित आयातों घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं। अभिभावी ए डी डी के क्रय विक्रय के बिना किया गया विश्लेषण दर्शाता है कि संबद्ध देशों से निर्यातों का पाटित कीमतों पर प्रवेश करना जारी है। संबद्ध देशों के विरुद्ध निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक तथा उल्लेखनीय है।

च. वृद्धि

73. घरेलू उद्योग के मात्रा और लाभप्रदता, दोनों मानदंडों ने क्षति अवधि में वृद्धि दर्शायी है।

ण. क्षति पर निष्कर्ष

74. प्राधिकारी ने नोट किया है कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में आधार वर्ष से 2015-16 तक गिरावट आई है, हालांकि, पी ओ आई के दौरान (वार्षिक आंकड़ों के आधार पर जांच की गई) आयातों में पिछले वर्ष अर्थात् 2015-16 की तुलना में वृद्धि हुई है किंतु आधार वर्ष की तुलना में निम्न बनी रही है। पी यू सी के कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा महत्वपूर्ण नहीं है और पूरी क्षति अवधि में गिरावट भी आई है। मात्रा भी कुल रूप में और भारत में उत्पादन और उपभोग के संबंध में निम्न रही है। जहां तक आयातों की कीमत प्रभाव का संबंध है, आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण नहीं किया है। घरेलू उद्योग के लिए कीमत कटौती और कीमत से कम बिक्री सकारात्मक है और आगे यह नोट किया गया है कि उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय सहित, घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित विभिन्न आर्थिक मापदंड बहुत सकारात्मक हैं, जबकि उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय संतुलित स्तरों पर है।

त. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना

घरेलू उद्योग का मत

75. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति वर्ग संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

क. पाटनरोधी शुल्कों को लागू किए जाने के बावजूद, संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन हो रहा है।

ख. संबद्ध देशों में निर्यातकों की उल्लेखनीय निष्क्रिय क्षमताएं हैं, जो भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, निर्यातकों द्वारा भारत में बाजार को अतिरिक्त क्षमताओं को भरने के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है।

ग. यदि शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी गई तो पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग के हिस्से में कमी आएगी।

- घ. संबद्ध देशों में निर्यातक निर्यात अभिमुखी है, जिनकी क्षमता घरेलू मांग से कहीं अधिक है।
- ङ. निर्यातक न केवल भारत में पाटन कर रहे हैं बल्कि अन्य देशों में भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध वस्तुओं को क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर तृतीय देशों को आपूर्ति की जा रही है। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन ज्यादा उच्च है।
- च. चूंकि भारत एक कीमत को आकर्षित करने वाला बाजार है और जब तक निर्यातक यह नहीं दर्शाते कि उनके अन्य बाजारों में कोई वचनबद्धता है, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि निर्यातक अपनी वस्तुएं भारत में बेचने को प्राथमिकता देगा।
- छ. भागीदार उत्पादक द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा प्रभारित कीमतें बाजार स्थितियों द्वारा प्रभावित होती हैं और न कि उत्पाद की लागत द्वारा।
- ज. यदि घरेलू उद्योग पर आयातों की पहुंच कीमत को बहन करने के लिए दबाव जाता है, तो उसे वित्तीय हानि और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक वापसी का सामना करना पड़ेगा।
- झ. शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, आयात क्षति कारक कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करेंगे।
- ञ. हाल ही में समाप्त मध्यवर्ती समीक्षा में प्राधिकारी के जांच परिणामों में पहले ही क्षति की संभावना स्थापित की गई है।
- ट. पाटनरोधी शुल्क की स्थिति में, घरेलू उद्योग लाभ अलाभ कीमतों को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होगा।
- ठ. यदि शुल्कों को समाप्त किया जाता है तो याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के नकद लाभों में कमी होगी और इसकी वापसी ऋणात्मक होगी।
- ड. इस संबंध में तर्कों का उत्तर देते हुए, यह निवेदन किया गया कि जांच के बाद की अवधि के लिए आंकड़ों को मांगने और प्रत्येक निर्णायक समीक्षा मामले में इसे अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और यह केवल तभी आवश्यक होता है जब जांच की अवधि में पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन ऋणात्मक हो।
- ढ. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्यात आंकड़ों की सत्यवादिता के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के आरोप के उत्तर में, यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी साउदी अरब द्वारा निर्यातों के संबंध में और निर्यातकों के उत्तर के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दायर सूचना से सह-संबंध स्थापित करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के बीजक से बीजक निर्धारण को अपना सकता है।
- ण. विरोधी पक्षकारों के तर्कों का उत्तर देते हुए, घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि जब अन्य देश से आयात कोई वास्तविक क्षति का कारण नहीं है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि इन आयातों पर शुल्क के लागू न किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाएंगे।
- त. प्राधिकारी ने बहुत से मामलों में शुल्कों में विस्तार किया है चाहे उस समय घरेलू उद्योग संगत अवधि के दौरान क्षतिका सामना न कर रहा हो। कानूनी अनिवार्यता इस बात की है कि पाटनरोधी शुल्क को तभी लागू किया जाना चाहिए जब इस बात का साक्ष्य हो कि घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामस्वरूप क्षति की संभावना है।

#### विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के मत

76. पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन यहां नीचे संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं :-

- क. जांच के पश्चात की अवधि के आंकड़े दर्शाते हैं कि साउदी अरब से आयात की मात्रा में और गिरावट आई है और पाटन की कोई संभावना नहीं है।
- ख. याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े वृद्धिपूर्ण हैं निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि साउदी अरब से तृतीय देश को निर्यात कीमत वास्तव में याचिका में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की तुलना में उच्च है।
- ग. पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना को निर्धारित करने के लिए जांच के पश्चात की अवधि के लिए कोई आंकड़े नहीं उपलब्ध कराए गए हैं, जिन पर एक निर्णायक समीक्षा जांच के विचार किया जाना है।

- घ. चूंकि, याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादन का केवल 25.06 प्रतिशत स्थापित करता है, क्षति की पुरानवृत्ति की संभावना को याचिका में अंतर्निहित सूचना के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता।
- ङ. क्षति के जारी रहने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इस समय को क्षति नहीं है।
- च. असंबद्ध देशों से आयातों की मात्रा साउदी अरब से आयातों की तुलना में अधिक है। घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना, यदि कोई हो, उन देशों से आयातों के कारण होगी, जहां पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं हैं।
- छ. याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने के लिए ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रहा है कि शुल्क को समाप्त करने का परिणाम पाटन या क्षति की पुनरावृत्ति अथवा उसके जारी रहने में होगा। जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (VII) में उपलब्ध कराया गया है, महत्वपूर्ण क्षति का खतरा तथ्यों पर आधारित होगा, और केवल आरोप, अनुमान या दूरस्थ संभावना के आधार पर नहीं।
- ज. याचिकाकर्ता ने विद्यमान अधिशेष क्षमताओं, क्षमता परिवर्तन पर कोई आंकड़े और जांच के पश्चात की अवधि के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। केवल क्षमताओं की पिछली प्रवृत्तियों को संभावित विश्लेषण के लिए अपनाया नहीं जा सकता।
- झ. इसके अतिरिक्त, यू एस ए में अधिशेष क्षमताओं के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। जहां तक साउदी अरब का संबंध है, कोई नया साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है और इसकी बजाय याचिकाकर्ता ने मध्यवर्ती समीक्षा में प्राधिकारी के जांच परिणाम का आश्रय लिया है, जो चार वर्ष पुराना है।
- ञ. जांच शुरुआत के समय जांच की अवधि में परिवर्तन के कारण संबद्ध देशों से निर्यातों के लिए आंकड़ों को अद्यतित नहीं किया गया है।
- ट. वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में क्षति की संभावना के लिए कीमत आकर्षकता ही एकमात्र कारण नहीं हो सकती।
- ठ. यदि कीमत आकर्षकता पर याचिकाकर्ता का पूर्वानुमान स्वीकार किया जाना है, तो भारत को संबद्ध देशों से निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि होनी चाहिए, इस बात का ध्यान किए बिना कि शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी गई है अथवा नहीं।
- ड. याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों में निर्यातकों की कीमत निर्धारण तरीकों को स्थापित करने के लिए पूर्ण और सत्यापनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं।
- ढ. याचिकाकर्ता ने कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण के संबंध में अथवा संबद्ध देशों में माल सूचियों के स्तरों के संबंध में जांच संबंधी आंकड़ों की कोई पश्चात की अवधि उपलब्ध नहीं करायी है।
- ण. केवल यह तथ्य कि पाटन मार्जिन पूर्ववर्ती जांच में सकारात्मक था, पर्याप्त नहीं है और भारत में पाटित आयातों की वृद्धि का सुस्पष्ट प्रमाण होना चाहिए।
- त. डी सी डब्ल्यू लिमिटेड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्ट किया है कि आयात कोई खतरा नहीं है और कंपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में है।
- थ. घरेलू उद्योग के दावे का उत्तर देते हुए कि लगातार पाटन का इतिहास रहा है, यह तर्क दिया गया कि दावा वृष्टिपूर्ण था क्योंकि दूसरी निर्णायक समीक्षा में एस ए डी ए एफ और एस टी एम ई के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन ऋणात्मक था। किसी भी मामले में, ऐतिहासिक आकलन पर आधारित निर्णायक समीक्षा में पाटन की कोई धारणा नहीं है।
- द. घरेलू उद्योग का दावा कि तृतीय देशों में पाटन है, निराधार है क्योंकि किसी अन्य देश में सादी अरब के विरुद्ध कोई पाटनरोधी जांच नहीं किए गए हैं।
- ध. इसी प्रकार, साउदी अरब में उत्पादकों के पास 35 प्रतिशत तक की अतिरिक्त क्षमताओं के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है।
- न. साउदी अरब से आयातों की मात्रा किसी प्रकार के कीमत ह्रास या न्यूनीकरण को प्रेरित करने के लिए अमहत्वपूर्ण है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

77. प्राधिकार ने नियमावली के अनुबंध II (VII) की शर्तों में, पाटन की क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग के दावे की जांच की है। नियमावली के अनुबंध II के खंड (VII) में अन्य के साथ साथ चार कारकों के लिए व्यवस्था की गई है, जिन्हें ध्यान में रखे जाने की जरूरत है, अर्थात:-

- क. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर महत्वपूर्ण बढ़े हुए आयातों की संभावना की ओर संकेत करती है;
- ख. किसी अतिरिक्त निर्यातों को समाविष्ट करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त निर्यातक की क्षमता में मुक्त रूप से निस्तारणीय अथवा आसन्न उल्लेखनीय वृद्धि भारतीय बाजारों में महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना की ओर संकेत करता है।
- ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर उल्लेखनीय ह्रासित या न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा और जो और अधिक आयातों की मांग में वृद्धि कर सकते हैं; और
- घ. अनुच्छेद की माल सूचियों की जांच की जा रही है।

78. प्राधिकारी के संज्ञान में लाए गए सभी कारकों की यह निर्धारित करने के लिए जांच की गई है कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन या क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है। चूंकि, वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग में अपने आर्थिक मानदंडों में वृद्धि देखी है, यह निर्धारित करना अधिक संगत होगा कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, यदि प्रवृत्त शुल्कों को समाप्त कर दिया जाए। प्राधिकारी ने विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है जैसा कि पाटन या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग या अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। पी ओ आई के बाद की अवधि की जांच की गई और पाया गया कि पी ओ आई के बाद के छः महीने के दौरान संबद्ध देशों से कोई आयात नहीं हुआ है।

79. संभावना के पैरामीटरों की जांच निम्नानुसार है :-

i. संबद्ध देशों में उत्पादकों की अतिरिक्त अथशेष क्षमताएं और निर्यात प्रचालन

क. सउदी अरब

80. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि साउदी अरब के मामले में, एक मात्र उत्पादकता अर्थात एस ए डी ए एफ, की वृहत क्षमताएं हैं जबकि घरेलू मांग स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत से कम है, जैसा कि नीचे विवरण में दिया गया है :-

विवरण	क्षमता (मी. टन)
क्षमता	***
घरेलू बिक्रियां	***
निर्यात	***
अतिरिक्त क्षमता	***

ख. यू एस ए

81. जहां तक यू एस ए का संबंध है, याचिकाकर्ता ने सूचना प्रस्तुत की है और रिकार्ड पर प्रस्तुत आंकड़े दर्शाते हैं कि यू एस ए में निर्यातकों की 46,600 डी एस टी प्रतिदिन की निर्धारित क्षमता है और वे अपनी क्षमता का पूर्व रूप से उपयोग करने में असमर्थ हैं, जिस कारण उनके पास 15-25 प्रतिशत के समकक्ष की निष्क्रिय क्षमता है। इसके अतिरिक्त, यू एस ए उत्पादकों ने जांच की अवधि में पूरे विश्व में विभिन्न देशों को 7.43 मिलियन मी. टन कास्टिक सोडे का निर्यात किया है। यह स्पष्ट है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास वृहत युक्त निस्तारणीय क्षमता है।

ii. तृतीय देश निर्यात - मात्रा और मूल्य

82. जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा निवेदन किया गया है, भारत के अतिरिक्त अन्य देशों को संबद्ध देशों से निर्यातों से संबंधित आंकड़े दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों में निर्यातक संबंधित सामान्य मूल्य से निम्न कीमत पर अन्य देशों में उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं।



क. सउदी अरब

83. सउदी अरब से तृतीय देशों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि भारत के अतिरिक्त, प्रमुख बाजारों जैसे ग्रीक, इटली, बहरीन, टर्की और थाईलैंड को 64,935 मी. टन की सीमा तक उल्लेखनीय निर्यात किए गए हैं। जिसमें से 64,743 मी. टन की मात्रा सामान्य मूल्य से काफी कम कीमतों पर निर्यात की गई है। वास्तव में, भारत के अतिरिक्त, अन्य देशों को किये गये कुल निर्यातों का 99.71 प्रतिशत पाटित कीमतों पर किया गया है।

विवरण	मात्रा (मी. टन)	पहुंच कीमत प्रति मीटन .	निर्यात कीमत प्रति मी टन .
ग्रीक	21,862	***	***
इटली	13,167	***	***
बहरीन	16,775	***	***
भारत	32,097	***	***

ख. यू एस ए

84. यू एस ए में निर्यातकों के लिए बहुत से अन्य देशों के अतिरिक्त आस्ट्रेलिया और मैक्सिको प्रमुख बाजार हैं जिन्हें 7,424,752 मी. टन मात्रा निर्यात की गई है जिसमें से 7,413,031 मी. टन भारत को की गई निर्यात कीमत से काफी कम कीमत पर निर्यात किया गया है। 99.84 प्रतिशत भाग भारत के अतिरिक्त अन्य देशों को पारित कीमतों पर निर्यात किया गया है।

विवरण	मात्रा (मी. टन)	पहुंच कीमत प्रति मी. टन	निर्यात कीमत प्रति मी. टन
ब्राजील	2,913,857	***	***
आस्ट्रेलिया	1,202,571	***	***
मैक्सिको	562,884	***	***
भारत	16,968	***	***

iii. वर्तमान और पिछले पाटन मार्जिन का स्तर

85. पूर्ववर्ती जांचों में पाटन मार्जिन का स्तर सकारात्मक है; और वर्तमान जांच में इस तरह से बना रहा है।

थ. कारणात्मक संबंध

86. अधिनियम की धारा 9क (5) के तहत, प्राधिकारी द्वारा पाटन की क्षति की संभावना और शुल्कों को जारी रखने की जरूरत की जांच करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य सूचीबद्ध ज्ञात कारकों द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने की संभावना है।

क. तृतीय देशों से आयात – जहां अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं की उल्लेखनीय मात्रा आयातित की गई है जैसे जापान, इण्डोनेशिया, ईरान और कतर, ऐसे आयातों की कीमत संबद्ध देशों की तुलना में काफी अधिक है। वर्तमान अवधि में घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना नहीं किया है।

ख. मांग में प्रवृत्ति – संबद्ध वस्तुओं की मांग क्षति अवधि में लगातार बढ़ी है। मांग में संकुचन घरेलू उद्योग को क्षति का संभव कारण नहीं है।

ग. अन्य उत्पादों का निष्पादन – क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उत्पादन, बिक्रियों की मात्रा, बिक्री कीमत, लागत, लाभों आदि से संबंधित आंकड़ों को पृथक किया गया है और केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में विश्लेषण किया गया है।

घ. उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन - इस अवधि में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में परिवर्तन नहीं हुआ है और यह सुझाव देने के लिए रिकार्ड पर कुछ उपलब्ध नहीं है कि इसमें परिवर्तन होने की संभावना है। इसलिए, खपत के पैटर्न में किसी परिवर्तन द्वारा घरेलू उद्योग की क्षति में अंशदान करने की संभावना नहीं है।

- इ. व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा – ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां नहीं हैं जो घरेलू उद्योग क्षति में अंशदान कर सकती हैं।
- च. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन – यह नोट किया गया है कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में न तो कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है न ही इसमें परिवर्तन की संभावना प्रतीत होती है। इसलिए प्रौद्योगिकी में परिवर्तन क्षति का संभव कारक प्रतीत नहीं होता।
- छ. निर्यात निष्पादन – प्राधिकारी ने उचित स्थानों पर निर्यात निष्पादन को पृथक किया है और इस प्रकार, संभावना से संबंधित विश्लेषण घरेलू उद्योग के केवल घरेलू निष्पादन पर विचार करते हुए किया गया है।
- ज. उत्पादकता – चूंकि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, इस बात की संभावना नहीं है कि यह गिरती हुई उत्पादकता के कारण क्षति का सामना कर सकता है।

व. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

87. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुई हैं। उनमें उठाये गए मुद्दों को पहले ही जांच के दौरान उठाया गया है और उसका उपयुक्त रूप से समाधान कर लिया गया है। तथापि स्पष्टता के लिए, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध की जांच नीचे दिए गए अनुसार की जा रही है:-

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

88. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

- क. क्षतिरहित कीमत की विस्तृत गणना को प्रकट नहीं किया गया है विशेषकर उस आधार पर जिस पर इसका निर्धारण किया गया है कि घरेलू उद्योग ने संसाधनों का अक्षमता से उपयोग किया है जिससे कि उसके सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया जाना आवश्यक हो गया है।
- ख. वास्तविक सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन घरेलू उद्योग को प्रकट किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि सामान्य मूल्य को याचिका प्रस्तुत करने वाली घरेलू उद्योग की कीमत पर तय किया गया है जबकि निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआई एण्ड एस आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इस कारण से इन गणनाओं को घरेलू उद्योग की हैसियत से गोपनीय के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ग. जिस तरीके से लाभ की गणना की गई है जिसमें वह तरीका शामिल है जिसमें नियोजित पूंजी की गणना की गई है, को कृपया प्रकट किया जाए। इसके अलावा जिस तरीके से कैपिटल बिजली की अंतरण कीमत का निर्धारण किया गया है उसे भी घरेलू उद्योग को कृपया साझा किया जाए।
- घ. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का लगातार और निरंतर पाटन हुआ है जो संबद्ध देशों में निर्यातकों की कीमत निर्धारण संबंधी व्यवहार को स्पष्ट रूप से आलोकित करता है। दोनों देशों में उत्पादकों के पास पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमतायें हैं जिसका उपयोग शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में भारत में मांग को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। अन्य देशों को 99 प्रतिशत से अधिक निर्यात भी पाटित कीमतों पर किए गए हैं। इस कारण से यदि ये शुल्क समाप्त हो जाते हैं तब संबद्ध देशों से भारत में आयात के बढ़ जाने की अत्यधिक संभावना है।
- इ. आयातों की मात्रा में पाटन रोधी शुल्कों के फलस्वरूप गिरावट आई है, उसके बावजूद संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होना जारी है। इसका यह अर्थ निकलता है कि यदि पाटन रोधी शुल्कों को जारी नहीं रखा जाता है तब घरेलू उद्योग आयातों की पहुंच कीमत को पूरा करने के लिए बाध्य होगा जिसका आशय यह होगा कि घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक लाभ प्राप्त होगा।
- च. यदि इन शुल्कों को हटा लिया जाता है तब आयातों को याचिका प्रस्तुत करने वाली घरेलू उद्योग की कीमतों से कम कीमत पर बेचना होगा और इसे लाभप्रद कीमत प्राप्त करने की अनुमति नहीं मिलेगी। वर्तमान समय में भी, याचिका प्रस्तुत करने वाले घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर अपर्याप्त लाभ अर्जित किया है। वर्तमान स्थिति से निवेश पर लाभ में किसी प्रकार की गिरावट का मतलब क्षति होगा।
- छ. एक मात्र कारण कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है यह है कि लागू पाटन रोधी शुल्कों ने आयातों की मात्रा पर रोक और घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान किया है।
- ज. सऊदी अरब से आयातों में कमी केवल इस कारण से हुई है कि एस टी एम ई, एस ए बी आई सी और एस ए डी ए एफ के बीच करार अगस्त, 2017 में समाप्त हो गया और अब इन सामानों का निर्यात के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। चूंकि एस ए डी ए एफ के माध्यम से इन सामानों का निर्यात करना व्यवहार्य नहीं था अतः करार के समाप्त होने के बाद आयात रुक गया था।

तथापि यदि पाटन रोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तब निर्यातक एस ए डी ए एफ भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटन को शुरू करने में नहीं हिचकेंगे।

- झ. सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग के लिए औसत लागत के आधार पर तय किया जाना चाहिए।
- ञ. शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को लगातार पाटन और क्षति के फिर से होने की बहुत अधिक संभावना है। लागू शुल्कों के बावजूद, घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभ कमाने में सक्षम नहीं हुआ है। यदि इन शुल्कों को हटा लिया जाता है, घरेलू उद्योग की स्थिति और खराब हो जायेगी।
- ट. एक निर्णायक समीक्षा जांच में कारणात्मक संबद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही यह सिद्ध कर लिया गया है कि शुल्कों को समाप्त होने के कारण घरेलू उद्योग को पाटन के फिर से होने अथवा इसके जारी रहने तथा क्षति होने की संभावना है, संभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणात्मक संबद्ध की मौजूदगी को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- ठ. प्राधिकारी ने इस पूर्वानुमान के अंतर्गत एन आई पी के निर्धारण के लिए जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों की अवधि में कच्चे मालों, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमताओं के न्यूनतम उपयोग पर विचार किया है कि संसाधनों के अकार्यक्षम उपयोग में अंतर है। इस प्रकार के दृष्टिकोण पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-III के पैरा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है। प्राधिकारी को सर्वप्रथम जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत में क्षति रहित कीमत के संबंध में पैरा-3 को ध्यान में रख कर अवश्य विचार करना चाहिए। पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुच्छेद-4 के संबंध में 'सर्वोत्तम उपयोग' पद्धति को केवल वहीं अपनाया जाए जब इस प्रकार के संसाधनों के अकार्यक्षम उपयोग द्वारा घरेलू उद्योग को हुई किस क्षति को निष्प्रभावी करने की आवश्यकता हो। तथापि जहां संसाधनों को कोई अकार्यक्षम उपयोग नहीं हुआ हो वहां न्यूनतम उपयोग का विचार किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है और प्राधिकारी को अवश्य ही पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-III के पैरा-3 के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। वर्तमान मामले में, कच्चा माल नमक है जो एक प्राकृतिक उत्पाद है और इसकी रासायनिक संरचना निर्धारित नहीं है। इसके कारण कच्चे मालों की खपत अलग-अलग अवधि में अलग-अलग होती है। हालांकि, कच्चे माल के उपयोग की किसी अकार्यक्षमता के कारण ऐसा नहीं होता है;
- ड. यदि क्षति रहित कीमत की गणना उस पद्धति के द्वारा की जाती है जिसका उल्लेख प्रकटन विवरण में किया गया है और जैसा कि समझा जाता है और जिसका पालन किया जाता है, प्रकट की गई क्षति रहित कीमत उस कीमत से बहुत कम है जिसे इस प्रकार से तय किया गया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कुछ समायोजनों अथवा कटौतियों को किया गया है अथवा घरेलू उद्योग के दावों को उस सीमा से अधिक अस्वीकार किया गया है जिसका प्रावधान अनुबंध-III में किया गया है। इस प्रकार का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से माने जाने योग्य नहीं है क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी वास्तविकता से कम उल्लेख की गई क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए अनुबंध-III में किए गए प्रावधान से आगे बढ़ गए हैं।
- ढ. यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अमरीकी डॉलर प्रति मी.ट. में व्यक्त निर्धारित मात्रा (शुल्क का निर्धारित रूप) सबसे अधिक उपयुक्त होगा।

#### विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

89. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं;

- क. यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करते हैं कि नियम-5 निर्णायक समीक्षा जांच पर लागू होता है अथवा नहीं। पाटन रोधी नियमावली का नियम-5 वर्तमान परिदृश्य में लागू है।
- ख. याचिकाकर्ता के पास जांच आरम्भन के लिए अपेक्षित आधार नहीं है। और वर्तमान समीक्षा जांच नहीं आयोजित करता है। कुल भारतीय उत्पादन का 25 प्रतिशत पर्याप्त नहीं है और इसे "बड़ा हिस्सा" नहीं माना जा सकता है। भारतीय घरेलू उत्पादकों के केवल एक वर्ग से सूचना के आधार पर छति का कोई आकलन उचित क्षति का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
- ग. यह प्रतीत होता है कि भारतीय घरेलू उत्पादकों का लगभग 75 प्रतिशत चल रही जांच में या तो रुचि नहीं रखता है अथवा वे इस प्रकार से रखे गए हैं कि उनके आंकड़े याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए आवेदन को नुकसान पहुंचावेंगे। एक अन्य सम्भव विकल्प यह है कि इन "समर्थकों" के आंकड़ों के फलस्वरूप अपेक्षाकृत पर्याप्त रूप में छति रहित कीमत को कैद करेगा और इस कारण से यह याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रचारित उद्देश्य के प्रतिकूल होगा।
- घ. याचिकाकर्ताओं ने केवल उन उत्पादकों का "चयन किया" है जिनके आंकड़े क्षति के कुछ स्तर को दर्शाते हैं और / अथवा इसके फलस्वरूप बहुत अधिक क्षतिरहित कीमत को तय करना होगा। क्षतिरहित कीमत को भारतीय उत्पादकों के केवल 25 प्रतिशत के

- आधार पर तय किया गया है और इस कारण से तय की गई क्षति रहित कीमत को बहुत अधिक चढ़ा बढ़ा कर पेश किया गया है और यह कुल मिलाकर भारतीय उत्पादकों की क्षति रहित कीमतों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
- ड. कुल भारतीय उत्पादन में से जी ए सी एल के उत्पादन को अलग करने के बाद भी, याचिकाकर्ता के पास पात्र उद्योग बनने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
- च. निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जांच की अवधि का एक हिस्सा अर्थात् अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 (जो प्रस्तावित जांच की अवधि और निर्दिष्ट जांच की अवधि पर ओवरलैप करता है) के संबंध में भी आंकड़े थे।
- छ. प्राधिकारी ने सऊदी अरब के लिए सामान्य मूल्य का आकलन सही रूप में नहीं किया है और इस कारण से इसने उसी के संबंध में पाटन मार्जिन का आकलन सही रूप में नहीं किया है। सऊदी अरब से निर्यात जांच की 15 महीने की लम्बी अवधि में से केवल 3 महीनों की एक अवधि (अप्रैल से जून, 2016) के लिए हुआ था और इस कारण से सामान्य मूल्य को केवल उस अवधि के लिए प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तय किया गया है। अप्रैल-जून, 2016 के लिए आंकड़ों के बजाए जांच की अवधि के आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य का प्राधिकारी द्वारा निर्धारण पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-6 के अनुसार नहीं है। इस बात का कोई औचित्य नहीं उपलब्ध कराया गया है कि किस प्रकार से 3 महीने की अवधि के लिए निर्यात की कीमत के साथ 15 महीनों की एक अवधि के दौरान सामान्य मूल्य की तुलना को पाटन रोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार "उचित" माना जा सकता है।
- ज. प्राधिकारी का यह समझ सही नहीं है कि माह-वार आधार पर सामान्य मूल्य पर इस प्रकार से विचार इस तथ्य के बावजूद किसी पूर्व जांच में नहीं किया गया है कि आयात जांच की पूरी अवधि के दौरान नहीं हुई थी। अन्य जांचों जैसे जापान और थाइलैंड से फिनायल और यूरोपिय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से फिनायल में ऐसा किया गया है। माननीय सेस्टेट द्वारा आक्सो अल्कोहल इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में उचित प्रथा के रूप में इसे भी माना गया था।
- झ. विचाराधीन जांच की अवधि में, भारत में निर्यात में निहित व्यापार माध्यम वही व्यापार माध्यम है जो एक नकारात्मक पाटन मार्जिन के अध्यधीन है। इस प्रकार से ऐसे किसी निर्यातक जिन्होंने पूर्व निर्णायक समीक्षा जांच में नकारात्मक पाटन मार्जिन प्राप्त किया है के पक्ष में कोई पूर्वानुमान होना चाहिए।
- ञ. प्राधिकारी ने यह भी दावा किया है कि भाग लेने वाले उत्पादक जांच की अवधि की संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की एक अलग लागत का दावा नहीं किया। प्राधिकारी इसमें भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर विचार नहीं कर रहे हैं और इस कारण से उसके संबंध में उत्पादन की लागत का तिमाही ब्यौरा के होने अथवा न होने पर बिल्कुल विचार नहीं किया जा रहा है।
- ट. जांच के लिए प्राधिकारी का आधार सही नहीं है क्योंकि सामान्य मूल्य की उचित तुलना के लिए अनुरोध को इन आधारों पर अस्वीकार किया गया है कि सऊदी अरब से उत्पादक/निर्यातक उत्पादन की लागत का तिमाही ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातक के उत्तर को पहले ही अस्वीकार कर दिया है और इस कारण से सामान्य मूल्य को तय करना किसी भी स्थिति में उसके आधार पर नहीं है। याचिकाकर्ताओं से प्राप्त आंकड़ों जिसके आधार पर ऐसा कहा जाता है कि सामान्य मूल्य को तय किया गया है कि मांग उक्त याचिकाकर्ताओं से की जानी चाहिए थी अथवा वैकल्पिक रूप से आई एच एस कैमिकल्स से माह-वार आंकड़े सार्वजनिक अभिलेख में उपलब्ध नहीं है और इन पर विचार किया जाना चाहिए था।
- ठ. आई एच एस आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की वैश्विक बिक्री की कीमत में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई अर्थात् इस अवधि के अंत तक इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। इस प्रकार से जांच की समग्र अवधि के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करना सऊदी अरब के उत्पादक/निर्यातक के हितों के बहुत अधिक हानिकारक है।
- ड. प्राधिकारी का यह दावा कि इस प्रकार की तिमाही अथवा मासिक आकलन विगत मामलों में नहीं किया गया था यद्यपि ऐसे उदाहरण थे जहां जांच की पूरी अवधि के दौरान आयात नहीं हुआ था।
- ढ. याचिकाकर्ताओं को जांच की अवधि के दौरान किसी प्रकार की क्षति नहीं उठानी पड़ी। वर्तमान मामलों में याचिकाकर्ता को लगातार कोई क्षति नहीं हुई है और प्राधिकारी द्वारा आकलन केवल घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के फिर से होने की संभावना की जांच से संबंधित होना चाहिए।
- ण. प्राधिकारी ने इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कभी-कभी संबद्ध आयातों की जांच का संदर्भ लिया है कि क्या "पाटन अथवा क्षति" के फिर से होने की कोई संभावना है। पाटन के फिर से होने की संभावना अथवा क्षति के फिर से होने की संभावना सिद्ध नहीं कर पाने का आशय यह होता है कि प्राधिकारी लागू पाटन रोधी शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश करने की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तदनुसार हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे 'अथवा' के बजाए 'और' शब्द का प्रयोग करते हुए उपयुक्त कानूनी अधिदेश को रिकार्ड करें।

- त. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के लाभ, ब्याज पूर्व लाभ, नगद लाभ और निवेश पर लाभ के संबंध में प्रतिकूल तथ्यों को भी रिकार्ड किया है।
- थ. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एन आई पी) का आकलन सही रूप में नहीं दिया है और उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है।
- द. वर्तमान मामले में क्षति रहित कीमत को समर्थन करने वाले उत्पादकों के आंकड़ों को अलग कर जानबूझ कर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। याचिकाकर्ताओं को केवल उन उत्पादकों को शामिल करने के लिए चयन किया गया है जो उप-उत्पाद के रूप में क्लोरीन को मानते हैं क्योंकि उप-उत्पाद अथवा संयुक्त उत्पाद के रूप में क्लोरीन को मानने पर निर्भर करते हुए, क्षति रहित कीमत बहुत अधिक अलग-अलग होती है। याचिकाकर्ता वर्तमान मामलों में क्लोरीन को एक उप-उत्पाद के रूप में मानते हैं, इस प्रकार के बर्ताव के कारण याचिकाकर्ता की क्षति रहित कीमत बढ़ जाती है। जबकि भारत में अन्य उत्पादकों के मामलों में, उत्पादन की निर्धारित लागत को कास्टिक सोडा और क्लोरीन के बीच बांटा जाता है जहां क्लोरीन को एक उप-उत्पाद के बजाए एक संयुक्त उत्पाद के रूप में माना जाता है।
- ध. प्राधिकारी की यह मान्यता है कि क्षति का नहीं होना संबद्ध वस्तुओं के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्कों का एक परिणाम हो सकता है। तथापि इस प्रकार की मान्यता रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों द्वारा नहीं दर्शायी गई है और इस पर विचार नहीं किया गया है कि लागू अधिकांश शुल्कों को रद्द कर दिया गया है और याचिकाकर्ता के कार्य निष्पादन में किसी प्रकार की गिरावट इस प्रकार के शुल्क को रद्द किए जाने के बावजूद नहीं देखी गई है। पाटनरोधी शुल्क को अब इन 13 देशों में से 9 देशों के विरुद्ध वापिस ले लिया गया है और यह वर्तमान में सऊदी अरब सहित केवल 4 देशों के विरुद्ध लागू है। लगभग 9 स्रोतों से शुल्कों को रद्द किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं का कार्यनिष्पादन धनात्मक रहा है और उनका विकास भी बहुत अधिक हुआ है। इस कारण से सऊदी अरब की हैसियत से इन शुल्कों को लगातार लगाए रखना सार्थक नहीं है।
- न. लागू पाटन रोधी शुल्कों की मात्रा को शामिल करते हुए पहुंच मूल्य पर विचार किया गया है। जब पाटन रोधी शुल्क की मात्रा को शामिल करने पर विचार किया जायें तब कीमत में कटौती अथवा कम कीमत में वृद्धि नकारात्मक होगी।
- प. याचिकाकर्ताओं के आर्थिक मानदंडों में सुधार हो रहा है और वे अत्यधिक विकास को दर्शाते हैं। यह स्पष्ट है कि “लगातार क्षति” की कोई स्थिति नहीं है।
- फ. पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना को सिद्ध करने के लिए प्रमाण का दायित्व घरेलू उद्योग पर है और इसे निर्यातकों पर नहीं डाला जा सकता है। कोई सत्यापन योग्य अथवा पर्याप्त सकारात्मक साक्ष्य याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में उपलब्ध नहीं कराया गया है। पाटन रोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने पर पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण पाटित आयातों की वृद्धि की भविष्य की दर, संबद्ध देशों में स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य अथवा मौजूदा क्षमता में वृद्धि, कीमत पर दबाव / हास और अन्य संगत मापदंडों के साथ-साथ माल भंडार का विश्लेषण पर निर्भर है। आंकड़ों के न होने और इसमें उपर किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखकर, याचिकाकर्ता संबद्ध देश से आयातों के फिर से होने अथवा पाटन के फिर से होने अथवा इसके जारी रहने की संभावना को निर्णायक तरीके से सिद्ध नहीं कर पायें हैं।
- ब. पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा- (VII) के अनुसार संभाव सीमा तक संभावना के मानदंडों का आकलन यह दर्शाता है कि यह मानदंड “पाटन और क्षति के फिर से होने की संभावना” के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए संतोषजनक नहीं है। याचिकाकर्ता कोई पर्याप्त सत्यापन योग्य साक्ष्य और सूचना उपलब्ध नहीं करा पाये हैं अतः मौजूदा क्षमताओं अथवा क्षमतावर्धन के कारण क्षति की संभावना के संबंध में इसके दावे को पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- भ. जांच की अवधि के बाद की अवधि यह दर्शाता है कि सऊदी अरब से निर्यात शून्य रहा है और इस कारण से यह स्पष्ट है कि “संभावना” का दावा नहीं माना जायेगा। इस प्रकार से इस मानदंड के आधार पर, घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के फिर से होने की कोई संभावना नहीं है।
- म. कोई लगातार क्षति नहीं हुई है क्योंकि याचिकाकर्ता को जांच की अवधि के दौरान अपने महत्वपूर्ण आर्थिक मानदंडों के संबंध में कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी है और जांच की अवधि के बाद की अवधि का कोई आंकड़ा याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- य. याचिकाकर्ता की क्षमतायें अपने निजी घरेलू बाजार और वैश्विक निर्यात जिसे यह पूरा करता है, के लिए उपयुक्त नहीं है। एक मात्र उत्पादक के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इसकी तीसरे देश के निर्यात बाजारों में पर्याप्त बिक्री के साथ-साथ घरेलू बाजार में बहुत अधिक बिक्री हुई है। वास्तव में जांच की अवधि में, प्रतिवादियों की बिक्री का 90 प्रतिशत से अधिक बिक्री या तो सऊदी अरब के घरेलू बाजार में अथवा तीसरे देश के निर्यात बाजार में किया गया था। संबद्ध वस्तुओं का केवल एक मामूली प्रतिशत भारत में

बेची गई थी और/अथवा माल भंडार के रूप में रखी गई थी। ऐसी स्थिति में, उत्पादक के पास कोई निष्क्रिय क्षमता नहीं है जिसे आधिक्य अथवा अतिरिक्त के रूप में पढ़ा जाये।

- र. “आधिक्य क्षमता” का संदर्भ सऊदी अरब में घरेलू मांग के अलावा किसी अतिरिक्त क्षमता से नहीं है। इसके बजाए इसका संदर्भ निष्क्रिय क्षमताओं से है जिसका उपयोग भविष्य में पाटित कीमतों पर भारतीय बाजारों में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री और उत्पादन के लिए किया जा सकता है। वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है और प्रतिवादियों की क्षमता का उपयोग 90 प्रतिशत से अधिक है और प्रतिवादियों की बिक्री भी बहुत अधिक है।
- कक. सऊदी अरब से आयात भारत में उन कीमतों पर नहीं हो रहे हैं जिसका बहुत अधिक दबावकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ता हो और न ही ऐसी कोई संभावना है कि इस प्रकार के आयात भविष्य में भारत में ऐसी दबावकारी अथवा न्यूनकारी कीमतों पर होगी।
- खख. इसमें उत्पादक द्वारा रखी गई माल भंडारी बहुत कम है और इसमें जांच की अवधि तक के वर्षों के दौरान धीरे-धीरे कमी आ रही है।
- गग. उत्पादकों की तीसरे देश के भंडारों में बिक्री के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों पर विश्वास किया गया है। तीसरे देशों को बिक्री की मात्रा बहुत कम अर्थात् 64935 मी.ट है, इसमें उत्पादकों द्वारा सूचित की गई बिक्री की मात्रा लगभग 4-5 गुना है। इस कारण से रिकार्ड पर उपलब्ध आंकड़ों में निरंतरता नहीं है।
- घघ. किसी अन्य देश द्वारा सऊदी अरब से कास्टिक सोडा के संबंध में कोई पाटन रोधी जांच नहीं हुआ है। तीसरे देशों में पाटन के संबंध में दावे का समर्थन करने के लिए तीसरे देशों में निर्यात की कीमत के संबंध में याचिका के अनुबंध-4.3 में उपलब्ध कराये गए आंकड़े सही नहीं हैं और इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।
- ड.ड. भारत में वास्तविक पहुंच मूल्य के संबंध में उत्पादक के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर घरेलू उत्पादकों की क्षति रहित कीमत वास्तविक पहुंच कीमत से लगभग 15 प्रतिशत अधिक होगी। याचिकाकर्ता का क्षति रहित कीमत सऊदी अरब से तीसरे देश के बाजारों में निर्यात कीमतों की तुलना में कम है।
- चच. निर्णायक समीक्षा का क्षेत्र इस तथ्य के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने तक सीमित है कि क्या पाटन और क्षति के फिर से होने अथवा उसके जारी रहने की कोई संभावना है और उससे अधिक कुछ नहीं है। निर्णायक समीक्षा में, प्राधिकारी के पास शुल्क को अलग अलग रखने अथवा उसमें संशोधन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पूर्व में किए गए अनुरोधों को देखते हुए कि यदि प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन रोधी शुल्क का विस्तार करने का निर्णय लेते हैं, तब पाटन रोधी शुल्क की मात्रा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए बल्कि उसे उसी स्तर पर रखा जाना चाहिए जो वर्तमान में लागू है।
- छछ. कीमत आकर्षकता को वर्तमान वास्तविक मैट्रिक्स में क्षति की संभावना के लिए एक कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है सऊदी अरब/संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरे देशों में और भारत में निर्यात के बीच कीमत में अंतर बहुत अधिक है जिसके कारण पाटन रोधी शुल्क के लागू रहने अथवा न लागू रहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- जज. प्राधिकारी को इस प्रकार के गैरवृद्धि वाले कारकों पर विचार करना चाहिए और एक विशेष जांच परिणाम रिकार्ड करना चाहिए कि घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच में हुई कोई मामूली क्षति केवल गैरवृद्धि वाले कारकों के कारण हुआ है। याचिका प्रस्तुत करने वाली कंपनियों ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में कथित क्षति के लिए कार्यों की पहचान की है जिसमें संबद्ध देशों से आयात शामिल नहीं है।
- i. डी सी डब्ल्यू ने 2016-17 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया कि आयात एक घतरा नहीं है और कंपनी अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम है।
  - ii. डी सी डब्ल्यू ने वर्ष 2016-17 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया कि कास्टिक सोडा प्रभाग के लिए कारोबार में गिरावट इसके तमिलनाडू संयंत्र में पानी की कमी और साहूपुरम एकक में श्रमिक से संबंधित मुद्दों जिसके फलस्वरूप संयंत्र को बंद करना पड़ा, के कारण हुआ था।
  - iii. ग्रासिम ने 2016-17 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि इसके कास्टिक प्रभाग द्वारा उठाई गई क्षति के लिए कारण के रूप में विमोद्रीकरण है।
  - iv. एस आई ई एल ने 2016-17 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि प्रयोक्ता उद्योग को आयातों में गिरावट के कारण कास्टिक सोडा की आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ा।
  - v. एस आई ई एल ने मावना शुगर्स लि. के माध्यम से 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में इसके द्वारा उठाई गई क्षति के लिए एक कारण के रूप में कच्चे माल की उच्च लागत को उजागर किया है।

- झझ. आयातक ने कास्टिक सोडा की खरीद करने के लिए याचिका प्रस्तुत करने वाली कंपनियों सहित विभिन्न घरेलू उत्पादकों को बार-बार अनुरोध भेजा है और इस संबंध में 11 मार्च, 2016 को इकॉनोमी टाइम्स के सभी एडीसनों के माध्यम से कास्टिक सोडा लाय का 120000 डी एम टी का अनुरोध करते हुए रुचि की अभिव्यक्ति ( "ई ओ आई" ) प्रकाशित की जिसमें विभिन्न घरेलू उत्पादकों को आयातक के बार-बार किए गए अनुरोधों पर कोई अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।
- जज. भारत के पश्चिम कोस्ट से पूर्वी कोस्ट तक कास्टिक सोडा की ढुलाई से अल्युमिना के निर्माताओं को अनावश्यक कठिनाईयां और कच्चे माल की लागत में वृद्धि होती है। इसके कारण प्रयोक्ता उद्योग के लिए ढुलाई की लागत में वृद्धि होती है और अन्य देशों से कास्टिक सोडा की मांग में वृद्धि होती है जिसकी बहुत अधिक मात्रा में आपूर्ति के साथ-साथ ढुलाई की लागत कम हो जाती है जिसके फलस्वरूप अल्युमिना उद्योग के लिए कच्चे माल (कास्टिक सोडा ) की लागत अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इसके साथ साथ यह तथ्य कि कास्टिक सोडा की आपूर्ति में कमी होती है और इसके फलस्वरूप सभी व्यवहार्य स्रोतों से मांग में वृद्धि होती है जिसमें संबंध आयात शामिल है।
- टट. प्राधिकारी एक निर्णायक समीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं कर सकते हैं बल्कि यह जांच विस्तार की अवधि के समाप्त होने अथवा विस्तार का क्षेत्र से ही संबंधित है। कानून की यह स्थिति मध्यावधि समीक्षा और निर्णायक समीक्षा के संबंध में प्रावधानों को तुलनात्मक रूप में पढ़ने पर सामने आती है। जहां मध्यावधि समीक्षा में शुल्क के अलग-अलग होने और इसमें संशोधन किए जाने का उल्लेख है, निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी को "इस प्रकार के आरोपन की अवधि का विस्तार करने"की अनुमति दी गई है। इसमें चीन और थाईलैंड से ग्राइडिंग मीडिया बाल्स का उल्लेख किया गया है जिसमें हाल में इस दृष्टिकोण को सही ठहराया है। यूरोपीय संघ के विनियमन का भी उल्लेख किया गया था।

#### प्राधिकारी द्वारा जांच

90. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोधों को बार बार दोहराया गया है और उनका समाधान पहले ही पूर्व के प्रकटन के विवरण में कर दिया गया है। जिस सीमा तक नए दावे किए गए हैं और उन्हें संगत समझा गया है, विशिष्ट मुद्दों को उपर्युक्त जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर निराकरण किया गया है। इसके अलावा प्राधिकारी ने यहां नीचे दिए गए संगत सीमा तक और कहीं अन्य स्थान पर उनका समाधान न किए जाने पर हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है।
91. क्षति रहित कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में, यह नोट किया गया है कि पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार उस पर विचार किया गया है। पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-III में क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए प्रक्रिया दी गई है। इसमें पिछले तीन वर्षों की अवधि और जांच की अवधि के दौरान कच्चे मालों की सर्वोत्तम उपयोग पर विचार करने का प्रावधान है। प्राधिकारी अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकते हैं और निर्धारित नियमावली के विरुद्ध केवल इस कारण से कार्य नहीं कर सकते हैं कि घरेलू उद्योग का यह दावा है कि नियमावली का प्रयोग वर्तमान मामलों में करना उपयुक्त नहीं है। क्षति रहित कीमत के कार्य करने की पद्धति को प्रकट करने के संबंध में विशिष्ट मुद्दों का समाधान पहले ही घरेलू उद्योग को सीधे ब्यौरा देते हुए कर दिया गया है।
92. इस दावे के संबंध में कि एक निर्णायक समीक्षा जांच में कार्यात्मक संबंध स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, से प्राधिकारी सहमत नहीं है। पाटन रोधी नियमावली के प्रावधान इस संबंध में स्पष्ट नहीं है कि एक निर्णायक समीक्षा में भी, प्राधिकारी को "पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने और घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना"पर विचार करना अपेक्षित है। इस प्रकार से पाटन और क्षति को स्थापित करना साथ साथ चलता है और कारण बताने की आवश्यकता इस भाषा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पाटन रोधी कानूनों का लक्ष्य और उद्देश्य पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि यह केवल क्षति है जिसे एक अनुचित व्यापार प्रथा अपना कर पाटन द्वारा उत्पन्न की गई है जिसका समाधान पाटन रोधी तंत्र का उपयोग कर किया जा सकता है।
93. सामान्य मूल्य का आकलन करते समय सबसे अधिक कार्यक्षम घरेलू उत्पादक के आंकड़ों पर विचार करने के कारण पाटन मार्जिन के कम होने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य और तदनुसार पाटन मार्जिन पर विचार प्राधिकारी की विगत, सतत प्रथा के अनुसार की गई है।
94. हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि निर्णायक समीक्षा आरम्भ करना केवल इस कारण के अनिवार्य है कि घरेलू उद्योग द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकारी इस स्थिति से पूर्ण रूप से अवगत हैं। वर्तमान मामलों में जांच आरम्भ तभी किया गया था जब इस याचिका के तथ्यों और रिकार्ड का आकलन किया गया और उसे प्राधिकारी की विगत प्रथा के अनुरूप पाया गया। प्रथम दृष्टि में संतुष्ट होने पर, जांच आरम्भ करने के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के संबंध में, प्राधिकारी ने जांच आरम्भन सूचना जारी किया था। उसके पश्चात जांच अवधि को सबसे हाल की अवधि जिसके लिए सूचना

उपलब्ध थी को शामिल करने के लिए अद्यतित किया गया था। ईरान और जापान के संबंध में उनके विरुद्ध पाटन और क्षति का पर्याप्त साक्ष्य के न होने को देखते हुए कोई जांच आरंभ नहीं किया गया था।

95. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा जिन असंगतताओं का उल्लेख किया गया वे भूलवश त्रुटियां थी और उनका समाधान वर्तमान जांच परिणाम में किया गया है।
96. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि विगत हाल में अन्य देशों से शुल्कों से समाप्त किए जाने के बाद भी, घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन सकारात्मक रहा है और उनके विकास भी अधिक है। इस कारण से सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका की हैसियत से शुल्कों को लगातार लगाया रखना सार्थक नहीं है। इसके अलावा सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के आयातों का हिस्सा कुल आयातों में बहुत कम है।
97. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से निम्नलिखित कारणों से घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन के फिर से होने की कोई संभावना नहीं है:-
  - क. संबद्ध देशों से भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों का हिस्सा बहुत मामूली है और इसमें गिरावट भी आ रही है। अन्य देशों से आयात बहुत अधिक है और इसमें लगातार वृद्धि भी हो रही है।
  - ख. रिकार्ड पर उपलब्ध आंकड़े संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण कीमत पर किसी दबाव अथवा हास को नहीं दर्शाते हैं।
  - ग. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसके अलावा लाभ, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ, नगद लाभ और नियोजित पूंजी पर लाभ में सकारात्मक रूप से वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों में अधिक सुधार हुआ है।
  - घ. संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त की गई निवल बिक्री वसूली क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना में सतत रूप से अधिक होना जारी है। निवेश पर लाभ, लाभ और ब्याज पूर्व लाभ में क्षति की अवधि और जांच की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस प्रकार से कीमत के मानदंडों में प्रवृत्ति निर्णायक रूप से यह सिद्ध नहीं करता है कि घरेलू उद्योग के मानदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पाटित आयातों के कारण हुआ है। संयंत्र का बंद होना, विमौद्रिकरण, कच्चे माल की अधिक लागत जैसे कारक कारकों को क्षति के लिए, यदि कोई हो, घरेलू उद्योग पर प्रभाव पड़ सकता है।
  - ड. सऊदी अरब के एक मात्र उत्पादक द्वारा क्षमता में कोई विस्तार नहीं किया गया है और भाग लेने वाले उत्पादक का क्षमता का उपयोग इस के घरेलू बाजार और तीसरे देश के बाजारों में बिक्री के लिए 90 प्रतिशत से अधिक है। इस कारण से उत्पादक के पास कोई निष्क्रिय क्षमता उपलब्ध नहीं है जिससे घरेले उद्योग के लिए खतरा उत्पन्न होता हो।
  - च. इसके अलावा अतिरिक्त क्षमताओं के दावे के संबंध में, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि केवल अतिरिक्त क्षमताओं का होना क्षति के फिर से होने की संभावना को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
  - ख. निष्कर्ष
98. सभी हितवद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच की अवधि में किए गए अनुरोधों के संबंध में, उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष नीचे दिए गए अनुसार है:-
  - क. संबद्ध देशों से स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में आयातों की मात्रा में धीरे धीरे गिरावट आई है। भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा बहुत मामूली है और इसमें गिरावट भी आ रही है।
  - ख. वर्तमान मामलों में कीमत पर कोई दबाव / हास नहीं है। इसके अलावा कीमत में कटौती बहुत कम और मामूली है।
  - ग. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं संबंध में पाटन रोधी शुल्क कई अन्य देशों में भी लागू है। तथापि प्राधिकारी ने उन शुल्कों को रद्द कर दिया है और घरेलू उद्योग पर इस प्रकार से रद्द किए गए शुल्क का न्यूनतम प्रभाव है क्योंकि घरेलू उद्योग लागू पाटन रोधी शुल्कों को रद्द किए जाने के बावजूद अच्छा कार्य निष्पादन दर्शाया है।
  - घ. घरेलू उद्योग का आर्थिक और वित्तीय मानदंड ( मात्रा और कीमत दोनों ) स्थिर है और इसमें किसी प्रकार की गिरावट अथवा गिरावट की संभावना नहीं देखी जा रही है जिससे पाटन रोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक हो।
  - ड. कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का आर्थिक मानदंड यह दर्शाता है कि कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, वास्तव में घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने में सक्षम है और क्षति की समग्र अवधि और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक निवल बिक्री वसूली



- प्राप्त करने में सक्षम है। तथापि संयंत्र का बंद होना, विमौद्रीकरण, कच्चे माल की उच्च लागत जैसे कारकों में घरेलू उद्योग के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने की पूरी क्षमता हो सकती है।
- च. प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि इस उद्योग की क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री और समग्र लाभप्रदता क्षति के मौजूद होने अथवा क्षति की किसी संभावना को नहीं दर्शाते हैं।
- छ. प्राधिकारी द्वारा संभावना के विश्लेषण के संबंध में जांच किए गए कारक यह सिद्ध नहीं करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
99. प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य भी है कि पाटन रोधी शुल्क दिसम्बर, 2000 से सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध लागू रहा है और यह लगभग 18 वर्षों से लागू है। इस समय घरेलू उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ है और इसने अच्छा कार्य किया है, आयातों में गिरावट आई है और कुल मिलाकर यह नोट किया जाता है कि पाटन रोधी शुल्क ने अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए इसे लगाया गया था।
- ग. सिफारिशें
100. किए गए अनुरोधों और उठाये गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि यद्यपि विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देशों से भारत में सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग के समग्र स्वास्थ्य में सुधार आया है। घरेलू उद्योग में अन्य देशों से बढ़े हुए आयातों का सामना किया है जिस पर पहले पाटन रोधी शुल्क लगता था और इसने उसके बावजूद सकारात्मक रूप से कार्य निष्पादन किया है। रिकार्ड पर सूचना संबद्ध देशों से शुल्क को रद्द किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति के फिर से होने की किसी संभावना को नहीं दर्शाता है।
101. इस कारण से प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन रोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश नहीं करते हैं और इसके द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2017 के सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 55/2017-सीमा शुल्क (ए डी डी ) के द्वारा विचाराधीन उत्पाद पर लगाये गए पाटन रोधी शुल्क को जारी नहीं रखने की सिफारिश करते हैं।
102. इस आदेश के विरुद्ध के अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष किया जा सकेगा।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2018

(Final Findings)

**Subject: Final Finding Notification in the 3<sup>rd</sup> Sunset Review of Anti-dumping investigation concerning imports of 'Caustic Soda' originating in or exported from Saudi Arabia and USA**

**F. No. 7/16/2017-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) had initiated 3rd Sunset Review of Anti-dumping investigation concerning imports of 'Caustic Soda' (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from Saudi Arabia and USA (hereinafter referred to as the subject countries).

#### **A. BACKGROUND**

2. Whereas, the original investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan, United States of America and France was initiated by the Authority

vide Notification 56/1/99-DGAD, dated 26.5.2000. The Authority, vide preliminary findings dated 16.11.2000 recommended imposition of provisional duty, which was imposed by Notification No. 153/2000 – Customs dated 26.12.2000. The final finding was notified by the Authority vide Notification No. 56/1/99-DGAD dated 14.5.2001 recommending imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from Saudi Arabia, Iran, Japan, United States of America (USA) and France. Accordingly, Customs Notification No. 69/2011-Customs(ADD) dated 26.6.2001 was issued imposing the duties.

3. Whereas upon expiry of applicable duties at five years, the Authority initiated a sunset review and vide Final Finding Notification No. 15/29/2004-DGAD dated 1.8.2006 recommended continuation of duty. Accordingly, the same was notified vide Customs Notification No. 98/2006 dated 13.9.2006. Further, on 8.6.2010, a mid-term review was initiated in respect of imports from Saudi Arabia, Korea RP and USA, pursuant to which the Authority modified the quantum of duties levied vide Final Findings dated 7<sup>th</sup> July, 2011.
4. Upon completion of five years, 2<sup>nd</sup> Sunset Review investigation was initiated by the Designated Authority against the imports of Caustic Soda from Saudi Arabia, USA, Japan, Iran and France vide notification 15/28/2010 dated 2.9.2011. The Designated Authority vide Final Finding notification 15/28/2010-DGAD dated 31.8.2012 recommended continuation of anti-dumping duties against imports from Saudi Arabia, Iran and USA. The ADD against imports from Japan was recommended as Nil and ADD against imports from France was terminated. Accordingly, a customs Notification No. 49/2012 – Customs (ADD), dated 26.11.2012 was issued valid for a period of 5 years.
5. Another mid-term review was initiated by the Authority vide notification 15/19/2015 dated 22.1.2016, against the imports from USA, Iran and Saudi Arabia. The Designated Authority conducted detailed investigations in respect of three subject countries, i.e. Saudi Arabia, Iran and USA; and recommendations were issued vide notification No. 15/19/2015 dated 20.6.2017. The Authority recommended modifications in duty which were notified vide customs notification no. 39/2017-Customs (ADD) dated 23.8.2017.
6. Whereas M/s Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) on behalf of M/s DCW Limited, M.s Grasim Industries Limited (6 units) and M/s SIEL Chemical Complex (hereinafter also referred to as the petitioner) filed an application requesting initiation of sunset review of the anti-dumping duties earlier imposed and seeking continuation of duties against imports from Saudi Arabia, Japan, Iran and USA. The request was based on the grounds that the expiry of the measure was likely to result in dumping from that country and consequent injury to the domestic industry.
7. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation vide Notification No. 7/16/2017-DGAD dated 20.11.2017 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from the Saudi Arabia and USA (hereinafter referred to as the subject countries), and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. However, no investigation was initiated with respect to Iran and Japan in view of lack of sufficient evidence of dumping and injury against them. Further, the duties in force were extended by the Central Government upto 25.11.2018 vide Notification No. 55/2017 – Customs (ADD) dated 24.11.2017.
8. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

#### **B. PROCEDURE**

9. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation;

- i. The Designated Authority, under the Anti-Dumping Rules, received a written application from the petitioner on behalf of the domestic industry, requesting for continuation of anti-dumping duties against the imports of subject goods from Saudi Arabia, Iran, Japan and United States of America.
- ii. On receipt of a duly substantiated application, the Authority issued Initiation Notification No. 7/16/2017-DGAD dated 20.11.2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating 3<sup>rd</sup> sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of the subject goods originating in or imported from Saudi Arabia and the United States of America. No investigation was initiated against Japan and Iran, in view of lack of sufficient evidence of dumping and injury against them.
- iii. The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the sunset review investigations in accordance with Rule 6(2) along with the copy of the initiation notification and NCV petition .
- iv. The Authority forwarded copies of the Notification to the following known producers / exporters in the subject countries (whose names and addresses were made available to the Authority by the petitioner) and provided opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2) and Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules.
  - a. M/s Shell Trading (M.E.) Pvt. Ltd. (STME), Saudi Arabia
  - b. M/s Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi Arabia
  - c. M/s Saudi Petrochemical Company, Saudi Arabia
  - d. M/s Sahara Petrochemicals Company, Saudi Arabia
  - e. M/s Saudi Arabia's Sahara and Ma'aden Petrochemicals Company (SAMAPCO), Saudi Arabia
  - f. M/s MIDPOINT Chemical Company, USA
  - g. M/s US Akzo Chemicals Limited, USA
  - h. M/s Dow Chemcail Company, USA
  - i. M/s Tricon Energy, USA
  - j. M/s FMC Industrial Chemicals Group, USA
- v. Further on the request of certain interested parties, the Authority extended the time period for submission of Questionnaire responses by the interested parties up to 5.02.2018.
- vi. The following producer and exporter from Saudi Arabia have only filed a response to the exporters' questionnaire:
  - a. M/s Saudi Petrochemical Company (SADAF), (Producer) along with its exporter M/s Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi Arabia
- vii. The Authority forwarded copy of Notification to the following known importers / consumers of subject goods in India (whose names and addresses were made available to the authority by the applicants) and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter, in accordance with the Rule 6(4):
  - a. M/s Abhay Chemicals Limited
  - b. M/s Albright Wilson Chemicals Limited
  - c. M/s Arvind Mills Limited
  - d. M/s Birla Cellulose Limited
  - e. M/s Central Pulp Mills Limited
  - f. M/s Deepak Nitrite Limited
  - g. M/s Godrej Sopas Limited
  - h. M/s Gujarat Narmada Fertilizer & Chemicals Limited

- 
- i. M/s Gujarat state Fertilizer & Chemicals Limited
  - j. M/s Indian Farmer Fertilizer Coop. Limited
  - k. M/s Indian Oil Corporation Limited
  - l. M/s Jaysynth Dyechem Limited
  - m. M/s Link Pharma Limited
  - n. M/s Meghmani Organics Limited
  - o. M/s Narmada Chemature Petrochemicals Limited
  - p. M/s Nirma Limited
  - q. M/s Pab Chemicals (P) Limited
  - r. M/s Rama News Print & Papers Limited
  - s. M/s Rubamin Limited
  - t. M/s Sabero Organics Limited
  - u. M/s Torrent Gujarat Biotech Limited
  - v. M/s Transpek Silox Industries Limited
  - w. M/s National Aluminium Company Limited
  - x. M/s Cyanides & Chemicals Company
  - y. M/s Hitsu Industries Limited
  - z. M/s Adani Exports Limited
  - aa. M/s Adani Wilmar Limited
  - bb. M/s Libra Foams
  - cc. M/s Shri Ramachandran Straw Products Limited
  - dd. M/s Bilag Industries Private Limited
  - ee. M/s Daurala Organics Limited
  - ff. M/s C J Shah & Co.
  - gg. M/s Harish Kr. & Company
  - hh. M/s Hindustan Link & Resins Limited
  - ii. M/s Hindustan Level Limited
  - jj. M/s Vedanta Limited
- viii. Out of all the importers, only M/s Vedanta Limited filed a response. They have submitted response in importers' questionnaire format and also participated in the oral hearing and subsequently filed written submissions.
  - ix. The Government of Saudi Arabia also participated in the oral hearing, however, no written submissions were filed by them.
  - x. The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is April, 2016 – June, 2017 (15 months). However, injury analysis period covers 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the period of investigation.
  - xi. Transaction-wise imports data for the period of investigation and preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and the same has been relied upon for the purpose of analysis in this investigation.
  - xii. The Authority made available non-confidential version of the application, data, responses filed and all the submissions presented by interested parties, in the form of an inspection folder open for

inspection wherein NC version were provided to all the interested parties, wherever requested, as per Rule 6(7).

- xiii. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods.
- xiv. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority also provided opportunity to the interested parties to present their views orally in an oral hearing held on 7.5.2018. The parties, who presented their views in the oral hearings, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xv. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this Final Finding.
- xvi. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this Final Finding to the extent possible and verified the data / documents given by the domestic industry to the extent considered relevant and necessary.
- xvii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in this Final Finding.
- xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis were examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded these findings on the basis of the 'facts available'.
- xx. A Disclosure Statement was issued on 19.7.2018 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 25.7.2018 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- xxi. \*\*\* in this Final Finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1US\$=Rs. 67.46.

### **C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

#### **Views of the domestic industry**

10. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of product under consideration and like article:
  - a. The product under consideration for the purpose of the present investigation is the same as in the earlier investigations, that is, Sodium Hydroxide or Caustic Soda in all its forms, generally known as Caustic Soda. It is chemically denoted as NaOH, and is a soapy, strongly alkaline odourless liquid widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical.

- b. Caustic soda is produced in two forms – lye and solids. Solids can be in the form of flakes, prills, granules or any other form.
- c. Caustic soda is industrially produced as a 50% solution by variations of the electrolytic chlor alkali process, including the mercury cell process, diaphragm cell process and membrane cell process.
- d. As noted in the previous investigations, the product produced by the petitioning domestic industry is like article to that imported from the subject countries.

#### **Views of the opposing interested parties**

- 11. No submissions were made by the other interested parties with regard to the scope of product under consideration or like article.

#### **Examination by the Authority**

- 12. The product under consideration in the present sunset review investigation is Sodium Hydroxide (chemical nomenclature NaOH), commonly known as Caustic Soda, in all forms.
- 13. Caustic soda is an inorganic, soapy, strongly alkaline and odourless chemical and finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fiber, aluminium, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergent, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining etc. Caustic soda is produced in two forms, that is, lye and solids by three technological processes, namely mercury cell process, diaphragm process and membrane process. The verification revealed that the DI is mainly using membrane technology, in fact world over the membrane technology is only being used. For the purpose of the investigation, the difference in processes does not lead to a difference in product in terms of various characteristics.
- 14. Caustic soda is classified under Chapter 28 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 under Customs Heading 2815.11 and 2815.12. As per ITC eight digit classifications, the product is classified under the Customs Heading 2815.1110, 2815.1120 and 2815.1200. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
- 15. Since none of the opposing interested parties have made any comments or submissions with regard to product under consideration and like article, the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as that in the earlier investigations.

#### **D. LIKE ARTICLE**

- 16. With regard to like article, as noted in the earlier investigations, there are no significant differences in the subject goods produced by the Indian industry and that exported from the subject countries. Even though the product is produced through different processes, the subject goods produced by the Indian industry and that imported from subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. None of the opposing interested parties have disputed the claims made by the domestic industry in this regard.
- 17. The subject goods produced by the petitioner companies are being treated by the Authority as like article to the subject goods imported from the subject countries, within the meaning of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules.

#### **E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

##### **Views of the domestic industry**

- 18. Views and response of the domestic industry on domestic industry and standing are as follows:

- a. The application was filed by M/s Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) on behalf of the domestic industry. The following domestic producers have participated in the present investigation, by providing the necessary costing information:
  1. M/s DCW Limited, Sahupuram
  2. M/s Grasim Industries Limited, pertaining to their six plants placed at Vilayat, Rehla, Karwar, Renukoot, Veraval and Ganjam. They have not given information pertaining to their seventh plant at Nagda.
  3. M/s SIEL Chemical Complex, Rajpura
- b. The petitioner companies constitute 25.06% share of total Indian production and is supported by producers which constitutes 100% of Indian production. Therefore the Authority holds that applicant companies constitute eligible domestic industry, as defined in Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.
- c. Rule 2(b) does not provide the minimum threshold of major proportion in terms of a mathematical figure. Major proportion does not mean 50% or significantly more than 25% of Indian production. Moreover, in keeping with the provisions of Rule 23(1B), the provisions of Rule 5 are not applicable in case of a sunset review investigation.
- d. The Designated Authority has considered a proportion below 50% as a major proportion in several cases. M/s GACL is ineligible on account of being an importer also and on exclusion of their production, the participating producers account for 28% of the domestic production. Further, if production of those companies who treat chlorine as joint product is excluded, the share of petitioning companies shall constitute 36% of domestic production, which cannot be considered as insignificant.
- e. The petitioner companies have not claimed that the domestic industry is suffering continued injury and the claim of extension of anti-dumping duty is based on threat/likelihood of injury, hence, the scope of the domestic industry for the purpose of assessment of continued injury becomes secondary and less important.

#### **Views of the opposing interested parties**

19. The views of the opposing interested parties with respect to domestic industry and standing are summarized as follows:
  - a. Since the petitioner companies constitute only 25.06% of domestic production, they do not constitute a major proportion to qualify as domestic industry. In the earlier investigations, the petitioner companies constituted much more than 25% of the domestic production. In EC – fasteners, Appellate Body did not consider 27% as major proportion for constituting domestic industry. There is no reasonable basis to exercise discretion by DA to allow just 25% share as domestic industry.
  - b. Even in MTR, when the petitioner filed data for producers constituting 33%, the Authority had called for data to be filed for more producers, to bring the standing to 49.87%.
  - c. As per the list of petitioners, Grasim, Ganjam is a participating producer, whereas as per the Annexure to the petition disclosing standing of the petitioner companies, DCM, Jhagadia has been mentioned in place of Grasim, Ganjam. Thus, the claim of 25% not supported by reliable information.

#### **Examination by the Authority**

20. The various submissions made by the interested parties during the course of the present investigation with regard to standing of petitioner and considered relevant by the Authority are examined and addressed in terms of Rule 2(b) of Anti-Dumping Rules.
21. The application for the present investigation was filed by the petitioner, M/s Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI), on behalf of the domestic industry. It is noted that petitioner companies, that is M/s DCW Limited, M/s Grasim Industries Limited and M/s SIEL Chemical Complex constitute

25.19% of the domestic industry in the period of investigation. Further, it is noted that M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Limited (GACL) is importing the subject goods from the subject countries and hence is ineligible to be the Domestic Industry and its production will not be counted for the purposes of estimating total production of the subject goods in India. It is noted that production of the participating companies is significant, thus, the petitioner companies constitute domestic industry within the meaning of the Anti-Dumping Rules, and the requirements of standing under Rule 5 of the Anti-Dumping Rules are duly satisfied. The Authority has not accepted the argument of the petitioner that the production of companies treating chlorine as joint product may be excluded for the purpose of determining the standing of the petitioner companies.

22. As regards reference to M/s DCM, Jhagadia in one of the statements in the petition, the petitioner clarified that this is a typographical error and M/s Grasim, Ganjam has provided data and not M/s DCM, Jhagadia.
23. In view of the above and after due examination, the Authority holds that the applicant industries satisfy the standing requirements and constitute domestic industry under Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.

#### **F. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY**

##### **Views of the domestic industry**

24. Excessive confidentiality claimed by the foreign producer/exporter thereby handicapping it in making meaningful comments with regard to the responses filed. Inter alia, they have failed to disclose the list of sample documents relating to domestic sales, actual or indexed data relating to the selling price structure, capacity, indexed details of cost of production and details of raw materials used.

##### **Views of the opposing interested parties**

25. The Authority had already satisfied itself regarding their requests for confidentiality. The confidential treatment granted is based on the established practice of the DA. Moreover, the requests for disclosure made by the domestic industry were either unreasonable or made without application of mind.
26. The DI has claimed complete confidentiality regarding its own cost of production in Annexures 6.2 to 6.6 of the petition and has not even provided any summarization. In fact the DI has specifically stated that such information is 'business proprietary information and is not amenable to summarization'.

##### **Examination by the Authority**

27. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

#### **G. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

##### **Views of the domestic industry**

28. Responding to the arguments of the opposing interested parties, the domestic industry submitted as follows:
  - a. The period for which duty has been in force is irrelevant for determining whether there is a need for continuation of duties. The law provides for extension of duties if the cessation of such duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping or injury. Even as per the practice of other countries such as Canada, USA, Brazil and European Union, duties may continue to be in force for more than 15 years, even if there are no imports of the subject goods.



- b. As regards the argument that anti-dumping duties have been discontinued against 9 out of 13 countries initially attracting the levy, it was argued that this fact itself establishes that the duty has been extended only in those cases where cessation of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping or injury.
- c. The Authority has initiated the investigation only after receipt of a duly substantiated application filed by the petitioner, and thus, there is no force in the argument that the investigation should not have been initiated.

#### **Views of the opposing interested parties**

29. The following other miscellaneous submissions have been raised by the opposing interested parties:
- a. The duties have been in force for a period of 17 years. The domestic industry has received adequate protection by way of anti-dumping duties since 2000, and no further protection is required.
  - b. Initially, in 2000, anti-dumping duties were imposed against imports of subject goods from 13 countries. The duties have already been withdrawn against 9 out of these 13 countries and should be withdrawn against the subject countries as well.
  - c. The data relating to third country exports from Saudi Arabia provided by the petitioner is unreliable as the source of information has not been provided.
  - d. Relying on the decision of the Hon'ble High Court of Delhi in the case of Kesoram Rayon, the parties urged that it was not mandatory on the part of the Authority to initiate sunset review investigation, and the Authority was required to satisfy itself regarding whether the application received is duly substantiated.
  - e. The application filed by the petitioner proposed the period of investigation as 2016-17, whereas the investigation was initiated considering the period of investigation as April, 2016 to June, 2017. Thus, there has been a violation of the Rule 5 of the Anti-Dumping Rules since the investigation has been initiated without actually examining the data for the complete period of investigation.

#### **Examination by the Authority**

30. The specific submissions made by the opposing interested parties and considered relevant, are addressed by the Authority as below:
- a. As regards the continuation of duty beyond a period of 17 years, the Authority finds that the duties have been extended in the past only when it was found after investigation that there was likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of duty. The very fact that duties have been discontinued against 9 out of 13 countries against which they were imposed, and three out of five countries for which the present case was originally initiated, have been excluded, itself shows that the Authority has not extended any duty on the request of the domestic industry and has considered whether there was likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury if the duties are not continued against a particular country.
  - b. The veracity of the data provided by the domestic industry has been examined by the Authority, and the same has been considered only after the adequacy and accuracy thereof has been established.
  - c. The present sunset review has been initiated by the Authority after being prima facie satisfied regarding the need to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury, on receipt of a duly substantiated petition. The Authority has not initiated investigations considering such investigations as a mandatory requirement.

- d. As regards the change in period of investigation at the time of initiation, the Authority notes that the Rules do not necessitate that the period for which the investigation is conducted should be the same as the period of investigation for which petition was filed. The Authority had, before initiating, prime facie satisfied itself regarding the need to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury. The Authority, however, considered it appropriate to adopt a more recent period to determine likelihood of dumping and injury. The procedure followed by the Authority is in conformity with the consistent practice of the Authority in this regard. It is also noted that Rule 5 is not applicable for sunset review investigations and initiation of investigation is governed by Rule 23.

#### H. METHODOLOGY AND DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DUMPING MARGIN

31. The Authority sent questionnaires to the known exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. Only one producer in Saudi Arabia, namely M/s Saudi Petrochemical Company (SADAF) and its related exporter, M/s Saudi Basic Industries (SABIC) filed a response to the exporters' questionnaire. However, the participating exporter has reported that there were no exports by the company during the period of investigation.

##### Views of the domestic industry

32. The domestic industry submitted as follows with regard to the determination of normal value and export price:
  - a. The participating producer and exporter have not denied the dumping of the subject goods in India. If the data as per IHS Chemical reports is considered, it would be seen that the dumping margin is not only positive but also significant.
  - b. The additional information as required in questionnaires issued vide Trade Notice No. 5/2018 dated 28th February, 2018 should be called for as such information is relevant for the purposes of ongoing investigations as well.
  - c. Since the exporter, M/s Shell Trading Middle East Pvt. Ltd. (STME), has not filed a response, the response filed by the producer, SADAF should not be accepted and individual dumping margin should not be allowed.
  - d. While SABIC and SADAF have claimed to have no exports to India, there is no response from any other exporter from Saudi Arabia. Further, none of the producers/ exporters from USA have participated in the present investigation. Thus, the normal value for each country should be calculated on the basis of selling price as per Global Chlor Alkali Report (IHS Chemical), furnished by the domestic industry.
  - e. The export price should be determined on the basis of the data as per DGCI&S and adjustments towards ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight should be made as per best estimates.
  - f. Selling, general and administrative expenses and profit of the exporter must be adjusted for determination of export price, as per the consistent practice of the Authority.
  - g. Responding to the plea that normal value should be considered on the basis of the prices in the first three months of the period of investigation, it was argued that the Authority has not undertaken a month by month analysis of dumping margin and injury margin in the present case and thus, the fact that imports took place in only part of the period of investigation is irrelevant.
  - h. Responding to submissions of the other interested parties in this regard, it was highlighted that in the earlier investigations as well, the exporter has claimed normal value on a weighted average basis. Moreover, no difference in the level of trade was claimed in the earlier investigations. Thus, there is no reason for a change in the manner of determining the normal value in the present investigation.

- i. In response to the contention of the exporter that STME has no business interest in exports and has, thus, not participated, it was argued that current ownership of the producer is irrelevant in this regard. Unless the concerned exporter files a response to the exporters' questionnaire, the response filed by the producer cannot be accepted.
- j. The adjustments to export price have been claimed on the basis of industry experience and market information.
- k. The petitioner has made adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight to the CUIF price reported in the DGCI&S data, to determine price at the ex-factory level. Since none of the exporters exporting the goods during POI have participated in the investigation, it is requested that adjustments to export price may be made as per best estimates, in keeping with normal practice of the Authority.
- l. A fair comparison be made between the export price and normal value, at the same level of trade, at ex-factory level. For this, it is necessary that S&G expenses and profits of the exporter are also reduced for determining export price.

#### **Views of the opposing interested parties**

33. The submissions of the other interested parties with regard to the determination of normal value and export price are summarized hereunder:
  - a. SADAF made some exports to India through STME during the period of investigation. However, since the marketing agreement between SADAF and STME was valid only till 30th September, 2017, and thus, has no business interest in exports of subject goods and has not filed response in the present investigation.
  - b. The petitioner has not provided any evidence forming basis for adjustments made for determining export price, and thus, the investigations should not have been initiated on the basis of the petition filed.
  - c. Price is taken as per Chlor Alkali report for the period of investigation whereas exports has been made only during the first three months April to June 2016. Thus, there is no fair comparison as required in para 6 of Annexure I.
  - d. Normal value should also be adjusted to arrive at ex-factory level. Comparison between ex-factory normal value and ex-factory export price would demonstrate that there is no dumping from Saudi Arabia.
  - e. The data filed by the respondent should be used to compute the normal value and dumping margin.
  - f. Responding to the allegation of the domestic industry, it was submitted that there is no occasion for the exporters to claim a dumping margin in the response to exporters' questionnaire. In any case, the exporters have specifically claimed in their submissions that there is no dumping.
  - g. With regard to the requirements for additional information, it was submitted that Trade Notice No. 5/2018 was applicable only to investigations initiated after such 28<sup>th</sup> February, 2018.
  - h. As regards the claim of the domestic industry that selling, general and administrative expenses and profits of exporters must be reduced, it was urged that the domestic industry has already claimed an adjustment of 3% towards commission, which would be sufficient to cover such expenses and profits.

#### **Examination by the Authority**

34. The questionnaire response in the present case has been filed by M/s Saudi Petrochemical Company (SADAF) (producer) along with its related exporter M/s Saudi Basic Industries (SABIC). As per the response they have declared export of \*\*\* MT which is much less than the quantities obtained from the data from DGCI&S which is to the extent of 32,097 MT of caustic soda lye. It has been examined and found that the difference is on account of the fact that the exporter had invoiced the goods before the

POI , therefore not declared in Appendix 2, however, the goods landed in India during POI and hence captured in DGCI&S data.

35. It is seen that SADAF is the producer of the product under consideration and has sold goods to related exporter for exports to India. The said goods were exported to India by M/s Shell Trading Middle East Pvt. Ltd. (STME) who has not filed questionnaire response. The producer has stated that STME has sold off their share and are no more part of SADAF. Further, another related company of the producer, SABIC has claimed that it is an exporter of the product under consideration to India. However, the company has not exported subject goods during the POI. The price at which goods have been exported to India and a number of other information relevant to determination of export price is with STME, which has not cooperated with the authority. The authority considers that since STME has not filed questionnaire response, SADAF-STME cannot be granted individual dumping margin. Further, since SABIC has not exported the product to India during the POI, it cannot claim the status of exporter. Thus, the Authority is unable to determine individual dumping margin either for SADAF-STME or for SADAF-SABIC. The Authority determined the dumping margin for imports from Saudi Arabia on the basis of best available information.
36. The Authority finds no merit in the contention of the opposing parties that dumping margin should be calculated considering the normal value for the first three months only, as such a month-wise analysis has not been undertaken in any previous investigation relating to the subject goods, despite the fact that the imports were not present throughout the POI in a number of investigations. Further, the participating producer has not even claimed separate cost of production of the subject goods over the POI. Therefore, the normal value and export price are determined as under:

#### **I. NORMAL VALUE**

37. The Authority determined the normal value on the basis of the best available information, in terms of Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules. Accordingly, the normal value has been constructed considering the cost of production of most efficient Domestic Industry. Further, reasonable profit @5% of cost of production has also been added for constructing Normal Value.

#### **II. EXPORT PRICE**

38. The Authority has determined the export price in respect of imports from each of the subject countries on the basis of best information available in accordance with the Rules. For this purpose, the Authority has adopted the transaction-wise data procured from the DGCI&S and determined the export price considering all imports of the product under consideration in India. The export price has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight expenses and bank charges to determine ex-factory export price of the product under consideration.

#### **III. DUMPING MARGIN**

39. The subject goods are produced and traded in two forms namely lye and flake. However, as imports have been made only in lye form, accordingly, the normal value for lye form has been compared with net export price for calculation of dumping margin. After the analysis of the data, the dumping margin is worked out as mentioned in the table below.

S.N.	Country of Export	Constructed Normal Value	Net Export Price	Dumping Margin		
		US\$/MT	US\$/MT	US\$/MT	%	Range
1	Saudi Arabia	***	***	***	***	20-30
2	USA	***	***	***	***	105-115

40. The dumping margin so determined against the subject countries is positive for the Period of Investigation.

**I. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION****Views of the domestic industry**

41. The domestic industry has submitted as follows with regard to injury and causal link:

- a. While the imports during POI have declined as compared to the base year 2013-14 but when examined for the injury period on year to year basis, imports show increase during 2016-17 over 2015-16 and during 2015-16 over 2014-15. Further, the producers in the subject countries have excess capacities, which may be diverted to take over the market in India.
- b. While the imports are not very significant in relation to production or consumption, this is only the impact of the anti-dumping duties in force. In the event of expiry of duty, the imports are likely to increase.
- c. The volume of imports from Saudi Arabia have declined only for the reason that the agreement between STME and SABIC came to an end. While exports by STME attracted nil duty, the goods if invoiced by SABIC were chargeable to duty. Therefore, after the agreement came to an end, SABIC had no option but to stop exporting the product and await expiry of duty.
- d. The imports have been undercutting the prices of the domestic industry, which shows that in the event of cessation of duty, the domestic industry would face injury.
- e. If the domestic industry is forced to compete with the imports at their landed price excluding duty, its profitability would suffer.
- f. The landed price of imports is below fair selling price or non-injurious price of the domestic industry.
- g. While the production and capacities of the domestic industry increased, the increase in production is less as compared to the capacities created.
- h. While the market share of the domestic industry had been increasing upto 2015-16, it has decreased in the period of investigation.
- i. The average stock of the domestic industry increased over the injury period, upto 2015-16, although it has declined in the period of investigation.
- j. There has been an increase in the profits, cash profits and return on investment of the domestic industry due to the anti-dumping duties in force.
- k. The only reason the domestic industry did not suffer deterioration in its performance is that the volume of imports was low due to the duties in force.
- l. Regarding the arguments of the opposing interested parties, it is submitted that price suppression or depression during the injury period are relevant only in a case of a fresh investigation or a where there is continued injury.
- m. The contention of the exporter that injury margin should be determined on the basis of the non-injurious price in the first three periods was mala fide as no such claim was made in the past, when there were variations in prices.
- n. There is no requirement for evaluation of causal link in case of a sunset review investigation.
- o. Since the domestic industry has only claimed threat or likelihood of injury, water shortages, scarcity of raw material and other factors highlighted by the opposing interested parties are not relevant.
- p. When the domestic industry has not claimed actual injury, there can obviously be no causal link between the dumping and injury. The causal link would be relevant only in determining whether withdrawal of duty is likely to cause injury to the domestic industry.
- q. Responding to submissions in this regard, it was argued that the imports from other countries are at much higher prices than the subject imports. Thus, they did not cause injury to the domestic industry.

**Views of the opposing interested parties**

42. The submissions made by the opposing interested parties with regard to injury and causal link are as follows:
- a. Total imports from Saudi Arabia have declined in absolute terms and in relation to total imports as well as domestic production.
  - b. Majority of the imports have been made from the countries against which duty has been withdrawn.
  - c. There is no price suppression or depression as the domestic industry has been able to increase its selling price despite decline in cost and in landed price.
  - d. Even though price undercutting in the period of investigation was higher vis-à-vis 2015-16, the profits of the domestic industry increased between this period.
  - e. While the petitioner has not calculated any price undercutting for 2013-14 and 2015-16, positive price undercutting has been computed for the subject countries as a whole. Evidently, the calculations by the domestic industry are completely erroneous.
  - f. Since the imports have taken place only during the first three months, that is, April to June, 2016, the non-injurious price should be determined for that period and compared to landed value of the imports to ensure fair comparison between the two.
  - g. Despite the high price underselling, the domestic industry has been able to make record profits, indicating a severe breach in causality.
  - h. In spite of the increase in imports, all economic parameters of the domestic industry, including production, capacity, capacity utilization, sales, inventories, profits and return on capital employed, have witnessed an improvement over the injury period. Thus, there is no need for continuation of duty.
  - i. When the domestic industry has itself admitted that it has not suffered injury during the injury period, the claim that there is some decline in period of investigation as compared to previous year is irrelevant.
  - j. The injury margin should be calculated on a weighted average basis considering all transactions, and not on the basis of transactions that are below non-injurious price, as has been claimed by the petitioner.
  - k. If the domestic industry continues to be injured even after 14 years of duty, it is obvious that the injury is a result of extraneous factors.
  - l. DCW Limited has stated that it experienced a fall in the turnover of subject goods on account of water shortage in Tamil Nadu and the labour issues in Sahapuram, which led a plant shutdown. Grasim Industries Limited has mentioned in its Annual Report for 2016-17 that it suffered on account of demonetisation, while SIEL has admitted that high cost of raw material is the reason of injury thereto. Thus, the injury to the domestic industry has not been caused by the subject imports.
  - m. SIEL has reported that there was a shortage of caustic soda due to the decline in imports. Had the imports been preventing the domestic industry from increasing its sales, it should have been able to increase its sales volume with the duties in place.
  - n. The major consumer of the subject goods, that is the aluminium industry, is located at the eastern coast whereas the petitioning industry is located at the western coast. The high cost of transporting the goods from the western coast, increases the demand for imports.
  - o. The data provided by the petitioner is inconsistent, and incorrect. The demand in the petition and that in the Annexure do not reconcile. Further, the petitioner has not provided any information relating to return on investment.

- p. When the domestic industry had claimed in the petition that there is likelihood of injury due to imports from Saudi Arabia, Iran, Japan and USA, it cannot now claim that it is reasonable to assume causal link between injury and dumping from Saudi Arabia and USA only.
- q. The Authority has, in some past sunset review cases, concluded that the injury to the domestic industry was not on account of dumped imports, but other factors and therefore, the duties were not continued. Similarly, in the present case as well, the Authority should determine if there is a causal link between the alleged dumping and alleged injury to the domestic industry, if any.

### **Examination by Authority**

43. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties. However, the specific submissions made by the interested parties are addressed by the Authority as below:
  - a. For the purpose of injury analysis, the Authority has considered the data provided by the domestic industry after due verification to ensure its adequacy and accuracy.
  - b. The determination of NIP was done on the basis of data provided by the petitioner companies after due verification. It was noted that the domestic industry treated chlorine and hydrogen as by product. Chlorine Gas are liquefied for merchant sales or used captively in gas form to manufacture further value added product. For most of the units Chlorine is the bottle neck for the production of Caustic Soda, some time they are forced to shut down the plant in absence of sufficient storage capacity/sales of Chlorine. In most of the cases chlorine are cleared at loss or buyer has to be paid freight charges to collect the delivery. Domestic Industry claimed return on fixed assets used for the Chlorine and Hydrogen plant, since both are part of Caustic soda manufacturing process.
  - c. Factors prevailing in the injury period or period of investigation, such as scarcity of water, raw material, demonetisation and such are relevant only in a situation where there has been any deterioration in the performance of the domestic industry. When the domestic industry has not claimed any material deterioration in its performance on account of the dumped imports, the fact that there had been a shortage of water or plant shut down for any other reason, or that the domestic industry suffered on other accounts does not imply break in causal link. Similarly, when the domestic industry has been able to increase its market share, it cannot be said that there is injury on account of geographical disadvantages suffered by the domestic industry. It is only in cases where the domestic industry has suffered injury in the investigation period, but the injury is attributable to other factors, all such factors become relevant for examination. The present case is for consideration of threat/likelihood of injury to the domestic industry with cessation of anti-dumping duty.
  - d. As regards the contention of the parties that the profits have increased, despite price undercutting reducing in the period of investigation, the Authority notes that the positive price undercutting and underselling merely demonstrates that the landed price of imports is below the selling price and non-injurious price, implying that the domestic industry would have to sell below the non-injurious price and its profitability would decline in the event of cessation of anti-dumping duty.
44. Rule 11 of the Anti-Dumping Rules read with its Annexure – II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” While considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

45. Rule 23 of the Rules provide that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.
46. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries. For this purpose, the Authority has considered such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization and the magnitude and margin of dumping in accordance with Annexure – II of the Rules.

### **I. CUMULATIVE ASSESSMENT OF INJURY**

47. Annexure II (iii) of the Anti-Dumping Rules provides that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that: -
- the margin of dumping established in relation to the imports from each country/ territory is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively account for more than seven percent of the imports of like article, and;
  - Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
48. In the present case, the margin of dumping from each of the subject countries have been found to be more than the de minimis limit prescribed; the volume of dumped imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed; and the exports from the subject countries directly compete inter se and with the like goods offered by the domestic industry in the Indian market. Cumulative assessment of the effects of the dumped imports is appropriate in the light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product. The Authority, therefore, considers it appropriate to cumulatively assess the effect of dumped imports from the subject countries.

### **II. TOTAL DEMAND & MARKET SHARE**

49. For the purpose of assessment of the domestic consumption / demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same has been summarized below. Caustic soda is manufactured in two forms, lye as well as flake and both the forms are covered within the scope of the subject goods in the original as well as present review investigation.

SN	Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI	POI (A)
A	Volume of subject goods						
1	Petitioner companies	MT	***	***	***	***	***
1a	Trend	Indexed	100	124	146	184	147
2	Other Indian producers	MT	***	***	***	***	***
2a	Trend	Indexed	100	104	101	135	108
3	Imports from Subject Countries	MT	52,081	13,151	25,036	49,065	39,252
4	Imports- other countries attracting duties	MT	100,043	180,974	89,711	78,883	63,106
5	Imports-Other countries	MT	152,350	212,532	360,140	378,869	303,096
6	Total Demand	MT	2,756,353	3,048,528	3,176,062	4,047,653	3,238,122
B	Market Share in Demand						
7	Domestic Industry	%	***	***	***	***	***
7a	Trend	Indexed	100	112	129	129	129
8	Other Indian producers	%	***	***	***	***	***
8a	Trend	Indexed	100	93	88	92	92
9	Imports-Subject Countries	%	2	0	1	1	1
10	Imports- other countries attracting duties	%	4	6	3	2	2
11	Imports-Other countries	%	6	7	11	9	9



50. It is seen that the demand for the subject goods has been steadily increasing over the injury period and the POI. The sale of the Domestic Industry is increasing consistently during the entire injury period and the POI(A). The sale of other Indian producers has remained significant and increased continuously during the entire injury period and the POI(A). The imports from the subject countries has declined during the entire injury period and have increased slightly during the POI(A) when compared to the previous year. Similarly, the imports from countries attracting ADD excluding the subject countries has increased slightly during 2014-15 but thereafter decreased consistently during the rest of the injury period and the POI(A). The imports from rest of the countries has increased consistently during the entire injury period but has declined slightly during the POI(A) when compared to the previous year.
51. The market share of the sales of the Domestic Industry in total demand of PUC in India has remained almost same during the entire injury period and POI, however, the market share of the sales of other Indian producers in total demand of the PUC in India although slightly declining has remained significant. The market share of imports in total demand of the subject goods in India has been low throughout the injury period which may be due to the facts of ADD in force. The market share of imports from other countries attracting ADD & rest of the countries is not significant although it is more than the imports from the subject countries.

### **III. VOLUME EFFECT OF DUMPED IMPORTS**

52. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For this purpose, the Authority has relied upon the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods from the subject countries has been analyzed as under:

#### **a. IMPORT VOLUME, SHARE OF IMPORTS IN RELATION TO PRODUCTION AND CONSUMPTION**

53. The data relating to the volume of imports and share of imports are as given below:

SN	Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI	POI (A)
1	Total Demand	MT	2,756,353	3,048,528	3,176,062	4,047,653	3,238,122
2	Domestic production	MT	***	***	***	***	***
2a	Trend	Indexed	100	105	110	144	115
3	Imports						
3a	Imports-Subject Countries	MT	52,081	13,151	25,036	49,065	39,252
3a(i)	Saudi Arabia	MT	52,081	13,144	25,036	32,097	25,678
3a(ii)	USA	MT	-	7	-	16,968	13,574
3b	Imports – other countries attracting duties	MT	100,043	180,974	89,711	78,883	63,106
3c	Imports-Other countries	MT	152,350	212,532	360,140	378,869	303,096
3d	Total Imports	MT	304,474	406,657	474,887	506,817	405,454
4	Share in Imports in relation to total Imports						
4a	Imports-Subject Countries	%	17	3	5	10	10
4a(i)	Saudi Arabia	MT	52,081	13,144	25,036	32,097	25,678
4a(ii)	USA	MT	-	7	-	16,968	13,574
4b	Imports -countries attracting duties(excluding subject counties)	%	33	45	19	16	16
4c	Imports-Other countries	%	50	52	76	75	75
5	Share of imports from subject countries in relation to						
5a	Production	%	***	-	***	***	***
5a(i)	Trend	Indexed	100	-	50	50	50
5b	Consumption	%	2	0	1	1	1

54. It is seen that the demand of PUC in India has been increasing consistently throughout the injury period and the POI (examined on annualized estimates), however, imports from the subject countries have declined from base year to 2015-16, although during the POI (A) the imports have increased as compared to the previous year i.e. 2015-16. Share of imports from the subject countries in total imports of the PUC is not significant and also declining throughout the injury period but has increased slightly during the POI (A) when compared to previous years i.e. 2014-15 & 2015-16. The imports from other countries are significant and also increasing consistently. The share of imports in relation to production and consumption in India is almost negligible and also declining.

#### **IV. PRICE EFFECT OF DUMPED IMPORTS**

55. With regard to the effect of the alleged dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the domestic industry on account of the alleged dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

##### **a. PRICE UNDERCUTTING**

56. Price undercutting has been assessed by comparing the landed price of imports with the domestic selling price in India of the subject goods during the period of investigation. For this purpose, the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the ex-factory level has been adopted. In order to ensure fair comparison, only the selling price of caustic soda in lye form has been considered.

SN	Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
1	Landed price of imports	Rs./MT	22,804	22,761	24,880	23,371
2	Net sales realization of domestic industry	Rs./MT	***	***	***	***
2a	Trend	Indexed	100	97	95	99
3	Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
3a	Trend	Indexed	100	81	7	77
4	Price undercutting	%	***	***	***	***
4a	Trend	Indexed	100	86	7	79
5	Price undercutting Range	%	10-20	5-15	0-5	5-15

57. It is seen that the landed price of imports is lower than the selling price of the domestic industry. The imports from the subject country are below the selling price of the domestic industry throughout the injury period and POI indicating therewith that NSR of DI is consistently higher than the landed value.

##### **b. PRICE SUPPRESSION AND DEPRESSION**

58. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

SN	Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI
A	Caustic Soda in form of Lye					
1	Landed price of imports	Rs./MT	22,804	22,761	24,880	23,371
1a	Trend	Indexed	100	100	109	102
2	Cost of sales of domestic industry	Rs./MT	***	***	***	***
2a	Trend	Indexed	100	98	83	84
3	Selling price of domestic industry	Rs./MT	***	***	***	***
3a	Trend	Indexed	100	97	95	99
B	Caustic Soda in form of Flakes					
4	Cost of sales of domestic industry	Rs./MT	***	***	***	***
4a	Trend	Indexed	100	111	96	99
5	Selling price of domestic industry	Rs./MT	***	***	***	***
5a	Trend	Indexed	100	101	104	116

59. From the above, it is seen that the landed price of the imports increased till 2015-16, and thereafter declined in the period of investigation. By contrast, the selling price of the domestic industry, for caustic soda in lye form, has declined upto 2015-16, and increased in the period of investigation, notwithstanding a decrease in costs. Similarly, in the case of caustic soda in flakes form, the selling price of the domestic industry has increased over the injury period, even though the cost of such goods has marginally decreased vis-à-vis the base year. Therefore, the data on record does not show any price suppression or depression on account of dumped imports.

### c. PRICE UNDERSELLING

60. For the purpose of calculating the price underselling, the non-injurious price has been worked out, in accordance with Annexure – III of the Anti-Dumping Rules and compared with the landed value of the subject goods. In order to ensure a fair comparison, the non-injurious price has been calculated for the subject goods produced in the form of lye only.

Country	Landed value	Non-injurious price	Price Underselling		
	US\$/MT		US\$/MT	%	Range
Saudi Arabia	358	***	***	***	10-20
USA	323	***	***	***	20-30

61. From a comparison of the landed value with the non-injurious price, it is noted that the price underselling is positive, and the subject imports are at prices, significantly below the Non-Injurious Price.

## V. ECONOMIC PARAMETERS OF DOMESTIC INDUSTRY

62. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
63. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

**a. Profits and actual and potential effects on the cash flow**

64. The domestic industry has stated that with the duties in force, the domestic industry has moved into a situation of profits from its earlier situation of losses. Resultantly, profit before interest, cash profits and return on investment have also improved. However, the return on investment of the industry is at a modest level.

SN	Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI	POI (A)
1	Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
1a	Trend	Indexed	100	100	85	86	86
2	Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***
2a	Trend	Indexed	100	98	100	109	109
3	Profit / Loss	Rs./MT	(***)	(***)	***	***	***
3a	Trend	Indexed	(100)	(199)	2,915	5,677	5,677
4	Profit / Loss	Rs. Lacs	(***)	(***)	***	***	***
4a	Trend	Indexed	(100)	(117)	771	1,472	1,840
5	Profit before interest	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
5a	Trend	Indexed	100	69	219	350	437
6	Cash profits	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
6a	Trend	Indexed	100	108	369	523	653
7	Return on investment	%	***	***	***	***	***
7a	Trend	Indexed	100	64	179	284	284

65. It is seen that the profit, profit before interests, cash profits and ROI has increased positively and significantly showing improvement is the condition of DI.

**b. Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales**

66. The production, capacity, capacity utilization and sales of the domestic industry are as shown in the table below.

SN	Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI	POI (A)
1	Capacity	MT	***	***	***	***	***
1a	Trend	Indexed	100	119	129	175	140
2	Production	MT	***	***	***	***	***
2a	Trend	Indexed	100	122	144	185	148
3	Capacity utilization	%	***	***	***	***	***
3a	Trend	Indexed	100	102	112	106	106
4	Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
4a	Trend	Indexed	100	123	145	185	148

67. It is seen that the capacity, production and sales of the domestic industry have increased over the injury period. Further, the capacity utilization has also increased between 2013-14 to 2015-16, although it has witnessed a decline in the period of investigation when compared to previous year.

**c. Inventories**

68. The data relating to inventory of the subject goods is shown in the following table:

SN	Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI	POI (A)
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***	***
2	Closing inventory	MT	***	***	***	***	***
3	Average inventory	MT	***	***	***	***	***
3a	Trend	Indexed	100	97	102	84	84

69. From the above, it is noted that the average inventory situation of the Domestic Industry has improved during the injury period indicating better market placement of the domestic industry.

**d. Employment, wages and productivity**

70. The data relating to Employment, wages and productivity is shown in the following table:

SN	Particulars	UOM	2013-14	2014-15	2015-16	POI	POI (A)
1	Employees	Nos.	***	***	***	***	***
1a	Trend	Indexed	100	105	107	107	107
2	Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
2a	Trend	Indexed	100	108	137	169	135
3	Productivity per employee	MT	***	***	***	***	***
3a	Trend	Indexed	100	116	135	139	139

71. It is noted from the above table that the wages and number of employees of the domestic industry have increased. Productivity per employee has improved during the injury period and POI(A). The increase in productivity per employee indicates better efficiencies and increase in wages could be in response to the progressive state of normal market conditions with time.

**e. Magnitude of dumping and Dumping Margin:**

72. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry. The analysis undertaken without factoring the prevailing ADD shows that the exports from subject countries have continued to enter India at dumped prices. The dumping margin so determined against subject countries is above *de minimis* and significant.

**f. Growth**

73. Both the volume and profitability parameters of the domestic industry have witnessed growth over the injury period.

**J. CONCLUSIONS ON INJURY**

74. The Authority notes that the volume of imports from the subject countries has declined from base year to 2015-16, although during the POI (examined on the basis of annualized figures) the imports have increased as compared to the previous year i.e. 2015-16 but remained low as compared to base year. Share of imports from the subject countries in total imports of the PUC is not significant and also declining throughout the injury period. The volume has been low in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Insofar as the price effect of imports is concerned, the imports have not suppressed or depressed the prices of the domestic industry. The price undercutting and the price underselling is positive for the domestic industry. It is further noted that various economic parameters relating the performance of the domestic industry, including production, sales, capacity utilization, market share, profits, cash profits and return on investment have been quite positive, whereas the profits, cash profits and return on investment of the industry have been at modest levels.

**K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**

**Views of the domestic industry**

75. The submissions made by the Domestic industry with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are as follows:
- There is continued dumping of the subject goods, despite the imposition of anti-dumping duties.

- b. The exporters in the subject countries have significant idle capacities, sufficient to meet the entire demand in India. In the event of expiry of duty, the exporters are likely to utilize these surplus capacities to flood the market in India.
- c. If the duties were allowed to expire, the dumped imports would significantly increase, and the market share of the domestic industry would reduce.
- d. The exporters in the subject countries are export oriented, having capacities far in excess of the domestic demand.
- e. The exporters have not only been dumping in India, but also in other countries. Further, the subject goods have been supplied to third countries at prices below the non-injurious price. The dumping margin and injury margin in respect of countries other than India is far higher.
- f. Since India is a price attractive market and unless the exporters show that they have any firm commitments in other markets, it must be concluded that the exporter would prefer to sell its goods in India.
- g. It has been admitted by the participating producer that the prices charged thereby are influenced by the market conditions, and not cost of the product.
- h. If the domestic industry is forced to meet the landed price of imports, it would suffer financial losses and negative return on capital employed.
- i. In the event of cessation of duty, the imports would enter the Indian market at injurious prices.
- j. The likelihood of injury has already been established in the findings of the Authority in the recently concluded mid-term review.
- k. In the event of expiry of the anti-dumping duty, the domestic industry would not be able to charge even break-even prices.
- l. If the duties cease, the cash profits of the petitioning domestic industry reduce and its return would be negative.
- m. Responding to arguments in this regard, it was submitted that there is no requirement for calling data for post period of investigation and adopting the same in every sunset review case, and the same may be necessary only when the dumping margin or injury margin is negative in the period of investigation.
- n. In reply to the allegation of the interested parties regarding veracity of export data provided by the domestic industry, it was requested that the Authority may undertake invoice-by-invoice determination of dumping margin and injury margin in respect of exports by Saudi Arabia and to co-relate the information filed by the domestic industry to the response of the exporters.
- o. Replying to the arguments of the opposing parties, the domestic industry submitted that when the imports from other countries have not caused any actual injury, there is no likelihood that they would cause injury to the domestic industry in the event of non-imposition of duties on these imports.
- p. The Authority has extended the duties in a number of cases, even if the domestic industry was not suffering injury during the relevant period. The legal requirement is that anti-dumping duty should be extended if there is evidence that dumping and consequent injury to the domestic industry is likely.

#### **Views of the opposing interested parties**

76. The submissions of the other interested parties, with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury are summarized hereunder:
- a. Post period of investigation data shows that import volume from Saudi Arabia have further declined and, thus, there is no likelihood of dumping.

- b. The data provided by the petitioner is incorrect, and the data provided by the exporter would show that the export price to third country from Saudi Arabia is actually higher than the data provided in the petition.
- c. No data for post period of investigation has been provided to determine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, which should be considered in a sunset review investigation.
- d. Since the petitioners constitute only 25.06% of the domestic production, likelihood of recurrence of injury cannot be established on the basis of the information contained in the petition.
- e. There is no likelihood of continuation of injury because there is no injury at present.
- f. Volume of imports non-subject countries is higher than the imports from Saudi Arabia. Likelihood of injury to the domestic industry, if any is to be attributed to imports from countries which are not attracting anti-dumping duty.
- g. The petitioner has failed to provide concrete evidence proving that the discontinuation of duty would lead to recurrence or continuation of dumping or injury. As provided in para (vii) of Annexure – II to the Anti-Dumping Rules, threat of material injury shall be based on facts, and not merely on allegation, conjecture or remote possibility.
- h. The petitioner has not provided any data based on existing surplus capacities, capacity addition and any data for post period of investigation. The past trends of capacities alone cannot be taken for likelihood analysis.
- i. Further, no evidence has been provided in respect of surplus capacities in USA. As regards Saudi Arabia, no fresh evidence has been provided and instead, the petitioner has relied upon the findings of the Authority in the mid-term review, which is four years old.
- j. The data for exports from subject countries has not been updated following the change in period of investigation at the time of initiation.
- k. Price attractiveness alone cannot be a reason for likelihood of injury in the present factual matrix.
- l. If the petitioner's prognosis on price attractiveness is to be accepted, there should have been a considerable increase in the exports from the subject countries to India, irrespective of whether duties are allowed to expire or not.
- m. The petitioner has not provided complete and verifiable evidence to establish the pricing behavior of the exporters in the subject countries.
- n. The petitioner has not provided any post period of investigation data with respect to price suppression or depression, or with regard to levels of inventories in the subject countries.
- o. Merely the fact that the dumping margin was positive in earlier investigations is not sufficient, and there should be explicit evidence of increase of dumped imports into India.
- p. DCW Limited reported in its annual report that the imports are not a threat and the company is in a position to face international competition.
- q. Responding to the claim of the domestic industry that there is a history of continued dumping, it was argued that the claim was incorrect inasmuch as the dumping margin determined for SADAF and STME in the second sunset review was negative. In any case, there is no presumption of dumping in a sunset review based on historical assessment.
- r. The claim of the domestic industry that there is dumping in third countries is without any basis as there are no anti-dumping investigations against Saudi Arabia in any other country.
- s. Similarly, the claim of the domestic industry regarding excess capacities to the extent of 35% with the producers in Saudi Arabia is factually incorrect.

- t. The volume of imports from Saudi Arabia is miniscule to trigger any kind of price suppression or depression.

**Examination by the Authority**

77. The Authority has examined the contention of the Domestic Industry to examine likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, in terms of Annexure II (vii) of the Rules. Clause (vii) of Annexure II to the rules provides, inter alia for four factors which are required to be taken into consideration, viz.:
- A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
  - Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
  - Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
  - Inventories of the article being investigated.
78. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. Since in the present case, the domestic industry has witnessed a growth in its economic parameters, it is more relevant to determine whether injury to the domestic industry is likely to recur on account of dumping, if the duties cease to be in force. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury. The post POI was examined and found that during the six months of post POI there are no imports from the subject countries.
79. The examination of the parameters of likelihood is as follows:

**i. Excess surplus capacities and export orientation of producers in subject countries**

**a. Saudi Arabia**

80. The Authority notes that in case of Saudi Arabia, the sole producer, namely SADAF has large capacities whereas domestic demand is less than 50% of the installed capacity, as detailed below:

Particulars	Quantity (MT)
Capacity	***
Domestic sales	***
Exports	***
Excess capacity	***

**b. USA**

81. As regards USA, the petitioner has submitted information and the evidence on record shows that the exporters in USA have a nameplate capacity of 46,600 DST per day and are unable to fully utilize their capacities, having idle capacities to the tune of 15-25%. Further, USA producers exported 7.43 million MT caustic soda to various countries globally in the period of investigation. It is clear that the producers in the subject countries have huge freely disposable capacities.



**ii. Third Country Exports – Volume & Value**

82. The data relating to exports from the subject countries to countries other than India, as submitted by the petitioner, shows that the exporters in the subject countries are exporting the product in other countries at a price below respective normal value.

**a. Saudi Arabia**

83. On an analysis of third country exports from Saudi Arabia, it is found that apart from India, there are significant exports to major markets such as Greece, Italy, Bahrain, Turkey and Thailand to the extent of 64,935 MT, out of which quantity of 64,743 MT have been made at prices much below the normal value. In fact, 99.71% of the total exports to countries other than India, have been made at dumped prices.

Particulars	Quantity (MT)	Landed price per MT	Export price per MT
Greece	21,862	***	171
Italy	13,167	***	175
Bahrain	16,775	***	213
India	32,097	***	263

**b. USA**

84. For the exporters in USA, the major markets are Brazil, Australia and Mexico besides many other countries amounting to 7,424,752 MT out of which quantity of 7,413,031 MT have been made at prices much below the export price to India. The 99.84% of the exports to countries other than India have been made at dumped prices.

Particulars	Quantity (MT)	Landed price per MT	Export price per MT
Brazil	2,913,857	***	***
Australia	1,202,571	***	***
Mexico	562,884	***	***
India	16,968	***	***

**iii. Level of current and past dumping margin**

85. The level of dumping margin in the earlier investigations has been positive, and continues to be so in the present investigation.

**L. CAUSAL LINK**

86. Under Section 9A (5) of the Act, the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties. Further, the Authority has examined whether other listed known factors are likely to cause injury to the domestic industry.

- Imports from third countries – While significant volumes of the subject goods have been imported from other countries such as Japan, Indonesia, Iran and Qatar, the price of such imports is much higher than that from the subject countries. The domestic industry has not suffered injury in the present period.
- Trend in demand – The demand for the subject goods has been steadily increasing over the injury period. Contraction in demand is not a possible reason causing injury to the domestic industry.

- c. Performance of other products – For the purpose of injury analysis, the data relating to production, sales volume, selling price, cost, profits, etc. has been segregated and the analysis has been done with respect to the product under consideration only.
- d. Changes in pattern of consumption – The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change over the period, and there is nothing on record to suggest that it is likely to change. Thus, any change in pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.
- e. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers – There are no trade restrictive practices which may contribute to the injury to the domestic industry.
- f. Developments in technology - It is noted that the technology for production of the product has neither undergone any material change, nor does it appear to be likely to undergo a change. Developments in technology, therefore, do not appear to be a possible factor of injury.
- g. Export performance – The Authority has segregated export performance at appropriate places, and thus, the analysis of likelihood has been done considering only the domestic performance of the domestic industry.
- h. Productivity – As the productivity of the domestic industry has increased, it is unlikely that it may suffer injury on account of declining productivity.

#### **M. POST DISCLOSURE COMMENTS**

87. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. The issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. However, for the sake of clarity the submissions by the interested parties are being examined as below:

##### **Submissions by Domestic Industry**

88. The Domestic Industry made the following submissions:

- a. The detailed calculation of non-injurious price has not been disclosed, specifically the basis on which it has been determined that the domestic industry has utilized resources inefficiently so as to warrant consideration of best utilization thereof.
- b. The actual normal value, export price and dumping margin should be disclosed to the domestic industry. This is because the normal value has been constructed on the cost of the petitioning domestic industry, while the export price has been determined on the basis of DGCI&S data. Therefore, the calculations cannot be treated as confidential qua the domestic industry.
- c. The manner in which return has been calculated, including the manner in which capital employed has been computed may kindly be disclosed. Further, the manner in which the transfer price of captive power has been determined may kindly be shared with the domestic industry.
- d. There is continued and incessant dumping of the subject goods from the subject country, which clearly bring to light the pricing behaviour of the exporters in the subject countries. The producers in both the countries have sufficient freely disposable capacities, which can be utilized to meet the demand in India in the event of expiry of duties. More than 99% of the exports to other countries have also been made at dumped prices. Therefore, if the duties lapse, the imports into India from the subject countries are highly likely to increase.
- e. The volume of imports declined as a result of anti-dumping duties, the subject imports nevertheless continue to undercut the prices of the domestic industry. This implies that if the anti-dumping duties are not continued, the domestic industry would be forced to meet the landed price of imports, which would mean financial losses and negative return on capital employed.

- f. If the duties are removed, the imports would undersell the prices of the petitioning domestic industry and would not allow it to charge remunerative prices. Even at present, the petitioning domestic industry has earned inadequate return on capital employed. Any deterioration in return on investment from the present situation would mean injury.
- g. the only reason that the domestic industry has not suffered injury is that the anti-dumping duties in force kept a check on the volume of imports and afforded protection to the domestic industry.
- h. The imports from Saudi Arabia reduced only because the agreement between STME, SABIC and SADAF came to an end in August, 2017 and the goods could no longer be exported through STME. Since it was not viable to export the goods through SADAF, the imports ceased post the expiry of the agreement. However, if the anti-dumping duty is removed, the exporter SADAF would not hesitate in resuming the dumping of the subject goods in India.
- i. The normal value should be constructed on the basis of the average cost for the domestic industry.
- j. There is high likelihood of continued dumping and recurrence of injury to the domestic industry in the event of expiry of duties. Even with the duties in force, the domestic industry has not been able to earn adequate returns. If the duties are removed, the situation of the domestic industry would only deteriorate.
- k. There is no requirement of causal link in a sunset review investigation. Once it has been established that cessation of duties is likely to cause recurrence or continuation of dumping and injury to the domestic industry, there is no requirement to establish the existence of a causal link between the likely dumping and likely injury.
- l. The Authority has considered the lowest utilization of raw materials, utilities and production capacities over the period of investigation and preceding three years for determination of NIP, under a presumption that the difference is inefficient utilization of the resources. Such an approach is in violation of provisions of paragraph 3 of Annexure III to the AD Rules. The Authority must first consider, in terms of paragraph 3, the non-injurious price on the cost of production of the domestic industry for the POI. The “best utilization” method, in terms of paragraph 4 of Annexure III of AD Rules, may be resorted to only when there is a need to nullify any injury caused to the domestic industry by inefficient utilization of such resources. However, where there is no inefficient utilization of resources, consideration of lowest utilization is not justified and Authority must proceed on the basis of paragraph 3 of Annexure III of the AD Rules. In the present case, the raw material is salt which is a natural product and its chemical composition is not fixed. Because of this, the consumption of raw material varies over the period. However, the same is not owing to any inefficiency of utilization of the raw material;
- m. Even if the non-injurious price is calculated by the methodology explained in the Disclosure Statement and as is understood to be applied is followed, the non-injurious price disclosed is much lower than that so calculated. This clearly indicates that certain adjustments or reductions have been made or claims of domestic industry have been rejected beyond what is provided for in Annexure – III. Such an approach is clearly not tenable inasmuch as the Designated Authority has gone over and beyond that is provided in Annexure – III to calculate a much understated non-injurious price and injury margin.
- n. It is submitted that in the present case, fixed quantum (fixed form of duty), expressed in US\$/MT, would be most appropriate.

**Submissions by opposing interested parties:**

89. The opposing interested parties made the following submissions:

- a. It is unclear whether the Authority considers that Rule 5 applies to Sunset Review Investigations or not. Rule 5 of the AD Rules is applicable in the present scenario.

- b. The Petitioners do not possess requisite standing for the initiation and conduct of the present review investigation. 25% of total Indian production is not sufficient and cannot be considered “major proportion”. Any assessment of injury based on information from merely a quarter of the Indian domestic producers would be insufficient to make a reasonable injury determination.
- c. It appears that about 75% of the Indian domestic producers are either uninterested in the ongoing investigation or are so placed that their data would undermine the application made by the petitioners. Another alternative possible is that the data of these “supporters” would lead to the construction of a significantly lower NIP and therefore, be counter productive to the cause propagated by the Petitioners.
- d. The Petitioners have “chosen” only those producers whose data shows some level of injury and / or leads to the construction of a very high non-injurious price. NIP has been constructed on the basis of merely 25% of the Indian producers and therefore, the NIP constructed is highly exaggerated and is not reflective of the NIP of the Indian producers at large.
- e. Even after excluding GACL’s production from the total Indian production, the Petitioner’s do not have sufficient standing to be eligible industry.
- f. The Designated Authority had data only with respect to a portion of the POI – i.e. for April 2016 to March 2017 (which is the overlap over the proposed POI and the designated POI).
- g. The Authority has incorrectly assessed the Normal Value for Saudi Arabia and therefore, has incorrectly assessed the Dumping Margin with respect to the same. The exports from Saudi Arabia occurred only for a period of 3 months (April to June, 2016) out of the 15 month long Period of Investigation and therefore, the Normal Value should have been constructed based on data for that period alone. The Authority’s determination of the Normal Value based on the POI data rather than the data for the April-June, 2016 period is not in accordance with paragraph 6 of Annexure I of the Anti-dumping Rules. No justification has been provided as to how comparison of normal value over a period of 15 months with export price for a 3-month period can be considered “fair” in line with the provisions of the AD Rules.
- i. Authority’s understanding is incorrect that such consideration of normal value on a month wise basis has not been undertaken in any previous investigation despite the fact that the imports were not present throughout the POI. The same has been done in other investigations such as Phenol from Japan and Thailand as well as Phenol from EU, South Africa and Singapore. It was also held as the appropriate practice by the hon’bl CESTAT in *Oxo Alcohols Industries Association v. Designated Authority*;
- h. In the POI under consideration, the trade channel involved in the exports to India is the same trade channel that was subject to a negative dumping margin. Thus, any presumption should be in favour of such an exporter who has received a negative dumping margin in the previous sunset review investigation.
- i. Authority has also claimed that the participating producer did not claim a separate cost of production of the subject goods of the POI. The Authority is not considering the data supplied by the participating producers herein and therefore, the presence or absence of quarterly break down of the cost of production with respect to the same is not under consideration at all.
- j. The Authority’s basis for examination is incorrect in so far as the request for fair comparison of normal value is rejected on the grounds that the producer/exporter from Saudi Arabia did not provide quarterly break down of cost of production. This is so because the Authority has already rejected the producer / exporter’s response and therefore, the normal value construction is not based on the same, in any case. Data from the Petitioners, on the basis of which normal value is said to have been constructed should have been sought from the said Petitioners or alternatively the month-wise data from IHS Chemicals is available on the public record and should have been considered;
- k. The IHS data clearly shows that the global selling price of the subject goods increased substantially over the POI, almost doubling by the end of the period. Thus, consideration of

normal value on the basis of the entire POI is extremely prejudicial to the producer / exporter from Saudi Arabia;

- l. The Authority's claim that such quarterly or monthly assessment was not done in past cases even though there were instances where imports were not present throughout the POI.
- m. There is no injury being suffered by the Petitioners during the period of investigation. There is no continued injury to the petitioners in the present case, and the assessment by the Authority should relate solely to the examination of the likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- n. the Authority has casually referred to the examination of the subject imports with a view to determining whether there is a likelihood of recurrence of "dumping or injury". The failure to establish either the likelihood of recurrence of dumping or the likelihood of recurrence of injury means that the Authority cannot proceed to recommend the continuation of the anti-dumping duties in force. Accordingly, we request the Authority to record the appropriate legal mandate using the word "and" rather than "or".
- o. The Authority has also recorded contrary facts pertaining to the Petitioners' profits, profit before interest, cash profits and return on investment.
- p. The Authority has incorrectly assessed the non-injurious price (NIP) for the domestic industry and the same is overstated.
- q. the NIP in the present case has been willfully exaggerated by the exclusion of data of supporting producers. The Petitioners have been cherry picked to include only those producers who treat chlorine as by-product since depending on the treatment of chlorine as by product or joint product, the NIP varies substantially. The Petitioners in the present case treat Chlorine as a by-product, such treatment inflates the NIP of the Petitioners. While, in the case of other producers in India, the fixed costs of production are divided between caustic soda and chlorine, where chlorine is treated as a joint-product rather than a by-product.
- r. The Authority has presumed that the lack of injury may be an outcome of the anti-dumping duties in force against the subject goods. However, such a presumption is not reflected by the facts on record and fails to consider that the majority of the duties in force have been revoked and the petitioners' performance has shown no decline despite such duty revocation. The anti-dumping duty is now withdrawn against 9 out of these 13 countries and is currently in force against only 4 countries including Saudi Arabia. Despite the revocation of duties from as many as 9 sources, the performance of the Petitioners has remained positive and their growth is also significant. Therefore, the continued imposition of duties qua Saudi Arabia is not meaningful.
- s. The landed value has been considered by including the quantum of ADD in force. The price undercutting and price underselling when considered including the amount of ADD, would be negative.
- t. The Petitioners' economic parameters are improving and show significant growth. It is evident that there is no situation of "continued injury".
- u. The burden of proof to establish likelihood of continuation or recurrence of dumping lies with the domestic industry and cannot be shifted on to the exporters. No verifiable or sufficient positive evidence has been provided by the petitioner in this regard. The determination of likelihood of dumping and injury upon expiration of anti-dumping duties is dependent on the analysis of the prospective rate of increase of dumped imports, freely disposable or increase in existing capacity in the subject countries, price suppression/depression, and inventories along with other relevant criteria. In light of the missing data and submissions made hereinabove, the Petitioner has failed to conclusively prove a likelihood of recurrence or continuation of dumping of the Subject Country imports.
- v. An assessment of likelihood parameters as per paragraph (vii) of Annexure II of the AD Rules, to the extent possible, shows that these parameters are not satisfied for a conclusion of "likelihood of recurrence of dumping and injury". The Petitioner has failed to provide any

sufficient verifiable evidence and information, its claims regarding the likelihood of injury due to existing capacities or capacity addition should be completely disregarded.

- w. The post-POI period shows that exports from Saudi Arabia have been NIL and therefore, it is evident that the “likelihood” claim is bound to fail. Thus, based on this parameter, there is no likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- x. There is absence of continued injury as there is no injury suffered by the Petitioner with respect to its critical economic parameters during the POI, and no post POI data has been provided by the Petitioner.
- y. The capacities of the producer are suitable for its own domestic market and the global exports it caters to. The data of the sole producer shows that it has substantial sales in its domestic market along with substantial sales in third country export markets. In fact, in the POI more than 90% of the sales of the Respondents were made either in the domestic market of Saudi Arabia or in third country export market. Only a marginal percentage of the subject goods was sold to India and / or held as inventory. In such a situation, the producer has no idle capacity which may be read as excess or surplus.
- z. “Excess capacity” does not refer to any capacity over and above the domestic demand in Saudi Arabia. Rather, it refers to idle capacities that may be engaged, in the future, for production and sale of subject goods to the Indian markets at dumped prices. In the present case, it is evident that the producer do not hold any such capacity and the capacity utilization of the Respondents is more than 90% and even the sales of the Respondents are quite high.
- aa. The imports from Saudi Arabia are not entering India at prices that have a significant depressing or suppressing effect and neither is there any likelihood that such imports would, in the future, enter India at such suppressive or depressive prices.
- bb. The inventories held by the producer herein are miniscule and gradually reducing over the years upto the POI.
- cc. Reliance has been placed on the data provided by the Petitioners with respect to the producer’s sales to third country markets. The sales volume to third countries is as little as 64,935 MT, the sales volume reported by the producer herein is about 4-5 times that much. Therefore, there is inconsistency in the data on record.
- dd. There is no anti-dumping investigation on caustic soda from Saudi Arabia by any other country. The data provided in Annexure 4.3 of the Petition regarding export price to third countries to support claim concerning dumping in third countries is incorrect and unreliable.
- ee. Based on the data available with the producer regarding actual landed value in India, the NIP of the domestic producers would be about 15% higher than the actual landed value. The NIP of the Petitioners is lower than the export prices from Saudi Arabia to third country markets.
- ff. The scope of a sunset review is limited to arriving at a conclusion on whether there is a likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury and nothing more. In a sunset review, the Authority has no legal right whatsoever to vary or modify the duty. In view of the foregoing submissions that case the Authority decides to extend the anti-dumping duty with respect to the subject goods, then the quantum of anti-dumping duty should not be increased but maintained at the level that is currently in force.
- gg. Price attractiveness cannot be considered as a reason for likelihood of injury in the present factual matrix. The difference in price between Saudi Arabia/USA’s exports to the third countries, and India is very significant due to which the presence or absence of the anti-dumping duty would have no effect.
- hh. The Authority should take into account such non-attribution factors and record a specific finding that any slight injury suffered by the domestic industry in the present investigation is on account of the non-attributive factors alone. The Petitioning companies have identified in their Annual Reports the reasons for their alleged injury which are not inclusive of the imports from subject countries.

- i. DCW, reported vide its Annual Report of 2016-17 that the imports are not a threat and the company is capable of facing international competition.
  - ii. DCW vide its Annual Report for the year 2016-17 stated that the fall in turnover for the Caustic Soda Division was on account of water shortage in its Tamil Nadu plant as well as labour issues in the Sahupuram unit which lead to a plant shutdown.
  - iii. Grasim, vide its Annual Report 2016-17 clearly mentioned demonetisation as a reason for injury suffered by its Caustic division.
  - iv. SIEL's Annual Report for 2016-17 states that the user industry has experienced a shortage in the Caustic Soda supply due to the decline in imports.
  - v. SIEL via the Mawana Sugars Ltd, Annual Report 2016-17 highlighted high raw material cost as a reason for the injury suffered by it.
- ii. The Importer has sent repeated requests to various domestic producers including the Petitioning companies for procuring Caustic Soda and in this regard, published an Expression of Interest ("EOI") requesting 120,000 DMT of caustic soda lye vide all editions of Economic times on March 11, 2016. wherein the repeated requests of the Importer to various domestic producers have not received favourable responses.
  - jj. The transportation of caustic soda from the west coast to the east coast of India causes unnecessary hardships and increase in the cost of raw materials to the alumina manufacturers. This increase in transportation cost for the user industry would result in an increase in demand of caustic soda from other countries that have a lower cost of transportation along with supply of voluminous quantity leading to lower cost of raw materials (caustic soda) for the alumina industry. This coupled with fact that there is shortage of supply of Caustic Soda, results in an increase in demand from all viable sources which includes the subject imports.
  - kk. The Authority cannot recommend the imposition of a higher duty in a sunset review, rather, the investigation is concerned only with the scope of extension or cessation of the period of extension. This position of law emerges from a comparative reading of the provisions pertaining to mid-term review and sunset review. Where MTR speaks of varying or modifying the duty, the SSR provision allows the Authority to "extend the period of such imposition". Cited Grinding Media Balls from China and Thailand which has recently upheld this stance. EU regulation was also cited.

### **Examination of the Authority**

90. The Authority notes that most of the submissions by parties are repetitive in nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. To the extent fresh claims have been raised and considered relevant, the specific issues have been dealt with in appropriate places in the findings above. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere.
91. With respect to the Domestic Industry's claim pertaining to NIP, it is noted that the same has been considered as per Annexure III of the AD Rules. Annexure III of the Anti-dumping Rules codifies the procedure for the determination of NIP. It provides for consideration of best utilization of raw materials over the past three years period and the POI. The Authority cannot exercise discretion and act contrary to the prescribed rules, merely because Domestic Industry claims that application of rules is inappropriate in the present case. The specific issue relating to disclosure of NIP workings has already been dealt with by directly communicating the details to DI. Further, with regards to exporter's contention regarding wilful exaggeration of NIP working of DI, it is noted that the allegation is baseless and the NIP has been worked out on the basis of detailed verified information given by the petitioner companies of the applicant Association, who are considered eligible as per Rule 2(b) and 5(3) of the AD Rules.

92. With respect to the claim that there is no need to establish causal link in a sunset review investigation, the Authority disagrees. The provisions of the AD Rules are unambiguous that even in a sunset review, the Authority is required to consider the “likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry”. Thus, establishing dumping and injury goes hand in hand, and the requirements of causation are central to this language. Moreover, the object and purpose of anti-dumping laws are abundantly clear that it is only injury caused by dumping, an unfair trade practice, which may be addressed through the use of the anti-dumping mechanism.
93. With respect to the claim of the Domestic Industry regarding the dumping margin being low due to consideration of the data of the most efficient domestic producer while assessing the normal value, the Authority notes that the normal value and accordingly, the dumping margin has been considered as per the past, consistent practice of the Authority.
94. With respect to the claim of the interested party that initiation of sunset review is not mandatory simply because an application is presented by the Domestic Industry, the Authority is well aware of this position. The initiation in the present case was undertaken only after an assessment of the facts and record of the Petition and consistent with past practice of the Authority. Upon being prima facies satisfied, for the purposes of initiation, regarding the claims made by the DI, the Authority had issued the initiation notification. Thereafter the POI was updated to include the most recent period for which information is available. No investigation was initiated with respect to Iran and Japan in view of lack of sufficient evidence of dumping and injury against them.
95. The inconsistencies pointed out by the interested party were inadvertent errors and have been addressed in the present Findings.
96. The Authority has also noted that even after the revocation of duties from other countries in recent past, the performance of the domestic industry has remained positive and their growth is also significant. Therefore, the continued imposition of duties qua Saudi Arabia and USA is not meaningful. Further the share of imports of Saudi Arabia and USA is very miniscule in total imports.
97. Authority also notes that there is no likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry from the subject countries due to the following reasons:
- a. The share of imports from subject countries in relation to production and consumption in India is almost negligible and also declining. The imports from other countries are significant and also increasing consistently.
  - b. The data on record does not show any price suppression or depression on account of dumped imports from subject countries.
  - c. It is seen that the capacity, production and sales of the domestic industry have increased over the injury period. Further the profit, PBIT, cash profits and ROI has increased positively and showing significant improvement in the economic parameters of domestic industry.
  - d. The Net Sales Realisation achieved by the DI for the subject goods continues to be consistently higher than the landed value of the imports of the subject goods over the injury period and the POI. The Return on investment, profit and profit before interests has increased throughout the injury period and the POI. Thus the trend in price parameters do not conclusively establish that adverse impact on DI's parameters has been caused by dumped imports. The factors such as plant shutdown, Demonetisation, high raw material cost may be impacting the DI for injury, if any.
  - e. There is no capacity expansion by sole producer from Saudi Arabia and the capacity utilisation of participating producer is more than 90% for sales in its domestic market and third country markets. Therefore, there is no idle capacity available with the producer which poses a threat for the domestic industry.
  - f. Additionally, in respect of the claim of surplus capacities, it is important to note that mere existence of surplus capacities is not sufficient to establish likelihood of recurrence of injury.



**N. CONCLUSIONS**

98. Having regard to the submissions made over the course of this investigation by all the interested parties, the Authority, on the basis of the above facts, circumstances, and analysis, concludes as under:
- a. There is steady decline in the volume of imports from the subject countries in absolute and relative terms. The share of imports from subject countries in relation to production and consumption in India is almost negligible and also declining.
  - b. There is no price suppression / depression in the present case. Further, the undercutting is low and insignificant;
  - c. The Authority notes that the anti-dumping duties with respect to the subject goods were in force on many other countries as well. However, the Authority has revoked those duties and there is minimal impact of such revocations on the domestic industry as domestic industry has continued to perform well despite revocation of anti-dumping duties in force;
  - d. The financial and economic parameters of Domestic Industry (both volume and price) are stable and not evidencing deterioration or likelihood of deterioration requiring continuation of Anti-dumping Duty.
  - e. The link between the alleged dumped imports and the injury to the DI cannot be established as the economic parameters of the DI during the injury period and the POI demonstrates that there is no adverse impact on the health of the DI due to the alleged dumped imports, infact the DI is able to sell the subject goods and is able to achieve higher net sales realisation than the landed value of the subject goods during the entire injury period and the POI. However, factors such as plant shutdown, Demonetisation, high raw material cost may be potential enough to effect the health of the DI.
  - f. The Authority also holds that capacity utilisation, production, sales and overall profitability of the industry do not indicate existence of injury or a likelihood of injury.
  - g. The factors examined by the Authority w.r.t. likelihood analysis do not establish that there is injury to domestic industry.
99. The Authority is also cognizant of the fact that the anti-dumping duty has been in force against Saudi Arabia and USA since December, 2000 and has been in force for almost 18 years. In this time, the domestic industry has grown significantly and performed well, the imports have declined and overall, it is noted that the anti-dumping duty has served its intended purpose.

**O. RECOMMENDATIONS**

100. After examining the submissions made and issues raised, and considering the facts available on record, the Authority concludes that though the product under consideration has been exported to India from the subject countries below the normal value, it can be seen that the overall health of the domestic industry has improved. The domestic industry has withstood the increased imports from other countries, which were previously subjected to anti-dumping duties and has performed positively despite the same. The information on record does not show any likelihood of recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of duty from the subject countries.
101. Therefore, the Authority does not recommend continuation of the anti-dumping duty on the imports of subject goods from the subject countries and hereby recommends dis-continuance of the ADD levied on the PUC vide Customs Notification No. 55/2017 – Customs (ADD) dated 24 November, 2017.
102. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Director General